वर्ष: 7 अंक: 06

16-30 सितंबर, 2026 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

यूपीआई के 10 वर्ष

नया भारत दुनिया का 'पेमेंट गेटवे'

एक दशक में यूपीआई ने न केवल भारत में भुगतान का तरीका बदला, बल्कि दुनिया को डिजिटल पेमेंट की नई राह दिखाई, रोजमर्रा की जिंदगी से वैश्विक बाजार तक, यह तकनीक बनी आर्थिक आत्मविश्वास की नई पहचान...

हमें फॉलो करें @NISPIBIndia

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत

हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए प्रयासों को सामने लाते हैं। देशवासियों के इनोवेटेड आइडिया पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडिया ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। कई बार यहां से किए गए आह्वान जन-आंदोलन बन जाते हैं। कार्यक्रम की 137वीं कड़ी में उन्होंने नशा मुक्त भारत के मिशन से जुड़ने का आह्वान किया तो कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की। प्रस्तुत हैं संपादित अंश...

- **अनोखे विचार :** www.bharatrajya.com वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं कि किस समय, भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। यह प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, यह सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा।
- **नशा मुक्त भारत :** 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है - नशा मुक्त युवा, Drug Free India. बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं।
- **जागरूकता जरूरी, भूमिका निभाएं :** नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने - इस पवित्र कार्य में सभी अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को #नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें।
- **स्वनिधि योजना :** 'PM स्वनिधि योजना' की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं। देशभर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
- **स्वच्छता और जनभागीदारी :** इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में स्वच्छता और जनभागीदारी की प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर, हजारों स्वच्छता कर्मी दिन-रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान, 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को संग्रह और प्रोसेस किया गया।
- **Mission ShaktiSAT :** आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान, धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। Mission ShaktiSAT के माध्यम से 108 देशों की 12 हजार छात्राओं को सेटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
- **एवोकैडो फल :** आजकल एवोकैडो फल की बड़ी धूम है। इसे पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और मांग दोनों कम थी लेकिन आज यह स्वास्थ्य और प्रीमियम बाजार की पसंद है। हमारे किसान भाई-बहनों के लिए भी यह बहुत मददगार है।
- **महानायक उत्तम कुमार :** 3 सितंबर को महानायक उत्तम कुमार की जन्म-शताब्दी है जो एक बहुमुखी अभिनेता थे। वह अभिनय से लोगों के दिलों में रच-बस गए। हमेशा सब के दिलों पर राज करते रहेंगे। वे अपनी सहजता के साथ ही परोपकार के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख मिलती है।
- **वोकल फॉर लोकल :** त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर, आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दीये खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है।
- **आत्मनिर्भर भारत :** हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं, उसमें यह जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग, भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 7, अंकः 06 | 16-30 सितंबर, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

कतार से क्यूआर कोड तक

नए भारत की यूपीआई भुगतान क्रांति

आवरण कथा
यूपीआई के 10 वर्ष

बटुए से निकलते नोट, गल्ले में गिनकर रखे गए रुपये और एटीएम की कतार-यह सब अब भारत की एक पुरानी याद भर रह गए हैं। एक क्यूआर कोड, एक स्कैन और चंद सेकंड-आज देश के लेनदेन की यही नई भाषा है। दस वर्ष पहले अगस्त महीने में एक प्रयोग हुआ था, वह आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली बनकर भारत की पहचान बन चुका है। यह कहानी है उस बदलाव की, जिसने रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर बड़े व्यापारी तक, देश से लेकर विदेश तक, लोगों के जीवन को बनाया सुगम... | 8-20

अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ पीएम मोदी का संवाद

अंतरिक्ष में भारत की युवा शक्ति

'सेवा तीर्थ' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 स्पेस स्टार्टअप प्रमुखों से की मुलाकात | 28-29

समाचार सार | 4-5

गुणवत्ता-रफ्तार साथ-साथ
प्रगति की 53वीं बैठक की प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता | 6-7

चार मल्टीट्रैकिंग और एक हाइवे परियोजना को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय | 21

'आयुष्मान भारत' से सशक्त होता नया भारत
अब तक 47 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी | 22-23

राष्ट्रीय पोषण माह 2026 : पोषित भारत स्वस्थ भारत
'हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी' है 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की थीम | 24-25

जीडीपी : 7.8% रफ्तार से बढ़ी अर्थव्यवस्था
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने जीता आर्थिक मोर्चा | 26-27

रिफॉर्म्स... बाध्यता नहीं, प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास
इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को पीएम मोदी ने किया संबोधित | 30-31

मजबूत होता क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर
क्रूज भारत मिशन के दो वर्ष पूरे हो रहे, 32 राष्ट्रीय जलमार्ग ऑपरेशनल | 39

व्यक्तित्व : रानी रासमणि
साहस, करुणा और दृढ़ विश्वास की प्रतिमूर्ति | 40

खेलो इंडिया

खेल : युवा शक्ति को साथ जोड़ने का अभियान

पीएम मोदी ने 'खेलो इंडिया डायलॉग' में युवाओं को किया संबोधित | 32-33

पीएम की विदेश यात्रा

भारत-उज्बेक-किर्गिज संबंध

सांस्कृतिक जुड़ाव की मजबूत डोर

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी ने क्षेत्रीय संवाद और बहुपक्षीय साझेदारी को प्रदान की नई ऊर्जा | 34-38

प्रकाशकः कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल- response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812**

संपादक की कलम से...

यूपीआई के 10 गौरवशाली वर्ष

छोटी रेहड़ी हो या बड़ी दुकान... हो रहा यूपीआई से भुगतान

सादर नमस्कार

सुबह की सब्जी मंडी में ठेले वाला अब क्यूआर कोड दिखाता है। ग्राहक फोन से स्कैन करता है, चंद सेकंड में भुगतान हो जाता है। न नकद गिनने की झंझट, न बाकी पैसे लौटाने की चिंता। बिजली का बिल हो या दूध वाले का हिसाब, गली के नुक्कड़ की चाय की दुकान हो या शहर का बड़ा मॉल, हर जगह एक ही सुविधा, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान। यही है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की असली ताकत, जिसने आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना दिया है।

25 अगस्त 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में यूपीआई की शुरुआत की थी। अब यह सेवा अपने दस साल पूरे कर चुकी है और भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ बन गई है।

इन दस वर्षों में यूपीआई ने अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जहां मात्र 2 करोड़ लेनदेन हुए थे, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा 24,162 करोड़ को पार कर गया, यानी लगभग 12,000 गुना वृद्धि। इसी तरह लेनदेन की राशि 0.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ रुपये हो गई। शुरुआत में केवल 44 बैंक इससे जुड़े थे, अब 741 बैंक यूपीआई पर सक्रिय हैं। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई ने जोखिम आधारित लेनदेन सीमा और मजबूत सुरक्षा मानक लागू किए हैं। अब यूपीआई भारत के अलावा 11 अन्य देशों में भी काम कर रहा है। साथ ही, उज्बेकिस्तान में भी यूपीआई भुगतान सक्षम बनाने के लिए 30 अगस्त को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम भुगतान तंत्र बताया है। यह उपलब्धि भारत की डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता और समावेशी सोच का प्रमाण है, जिसने हर नागरिक को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ा है। यूपीआई की एक दशक की यात्रा ही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में साहस, करुणा और दृढ़ विश्वास की प्रतिमूर्ति रानी रासमणि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रगति की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर 'मन की बात' और बैक कवर पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

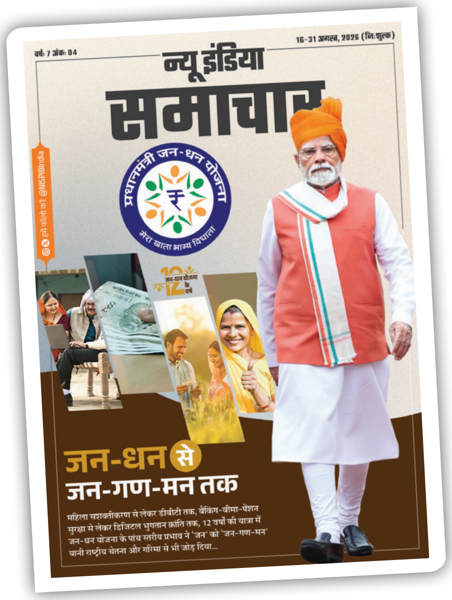

जागरूक करने में अहम भूमिका

मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। यह पत्रिका नेशनल पॉलिसी, डेवलपमेंट प्रोग्राम और सोशियो-इकोनॉमिक पहल पर अपडेट रहने में बहुत मदद करती है। पत्रिका साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और एरिया में हुए दूसरे डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से बताती है। इसे पढ़ने वालों को विकसित भारत के सफर की बेहतर समझ मिलती है। पत्रिका देश में हो रहे विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही है।

mihirtiwariabkp2002@gmail.com

सरकारी पहल, देश के विकास की जानकारी

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में सरकारी पहल, देश के विकास, पब्लिक वेलफेयर स्कीम और मौजूदा घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसे पढ़ने से छात्रों और देशवासियों को बहुत लाभ मिल रहा है।

library.bspp@ganpatuniversity.ac.in

जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए करती है प्रेरित

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका भारत की तरक्की की जानकारी देती है और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करती है। न्यू इंडिया समाचार ई-मैगजीन मुझे सरकारी नीतियों, कामयाबियों और विकास के बारे में जानकारी रखने में मदद करती है। यह आसानी से पढ़े जाने वाले फॉर्मेट में काम की और भरोसेमंद जानकारी देती है। यह पत्रिका मुझे एक जिम्मेदार नागरिक तो बनाती ही है और समझ भी बढ़ाती है।

सुयश चतुर्वेदी
suyash.chaturvedii@gmail.com

भारत की तेज ग्रोथ पर गर्व

जब भी मैं न्यू इंडिया समाचार पढ़ता हूं, मुझे सभी सेक्टर में भारत की तेज ग्रोथ पर बहुत गर्व होता है। भारत, कई मुश्किलों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दूसरे देश भी हमें हैरानी से देखते हैं और तारीफ करते हैं।

प्रो. पी. प्रेमा, तंजावुर
prof.prema@gmail.com

पत्रिका से कई अनजान और जरूरी बातें सीखी

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका बहुत बेहतरीन है। मैंने पहले इस पत्रिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे यह बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इस पत्रिका से कई अनजान और जरूरी बातें सीखी हैं। मैं इस पत्रिका की कामयाबी की कामना करता हूं।

श्री कृष्ण दत्ता
19duttakrishna@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

100 रुपये के प्रीमियम पर मिला 50,600 रुपये का मुआवजा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) पूरे देश में सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बीमारियों, बुआई न हो पाने, स्थानीय आपदाओं, बेमौसम बारिश और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर व्यापक बीमा कवरेज देती है। वर्ष 2016 से शुरू इस योजना से अभी तक 92.4 करोड़ आवेदक किसान लाभांवित हुए हैं। 2.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

पीएमएफबीवाई की ताकत का अंदाजा आप असम के चनखला गांव के छोटे किसान अनवर हुसैन की कहानी से लगा सकते हैं। भारी बारिश से उनकी फसल को नुकसान पहुंचा। अच्छी बात यह थी कि अनवर ने 100 रुपये का मामूली प्रीमियम देकर पीएमएफबीवाई में अपना पंजीकरण कराया हुआ था। इसकी वजह से उन्हें 50,600 रुपये का मुआवजा मिला। आर्थिक तंगी में फंसने के बजाय आत्मविश्वास के साथ खेती जारी रखने वाले अनवर कहते हैं कि पीएमएफबीवाई मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।

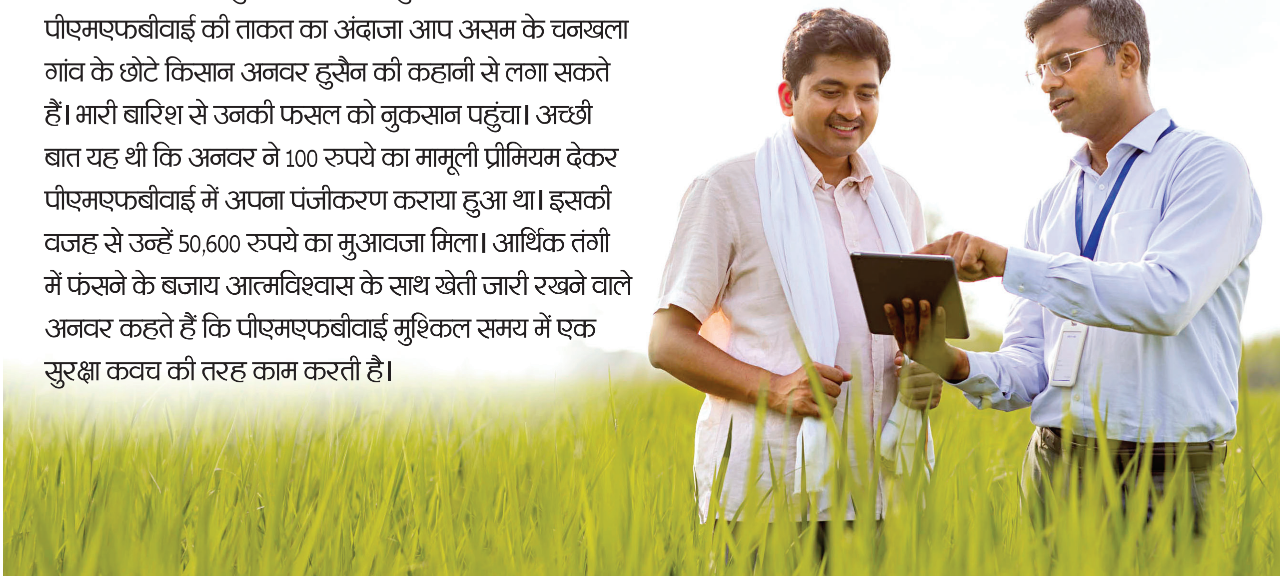

संचार साथी से एक ही महीने में 77,000 से अधिक मोबाइल बरामद

मोबाइल फोन गुम होने या चोरी होने की घटना आपके साथ घटित हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में सरकार की नागरिक-केंद्रित पहल 'संचार साथी' के यह आंकड़े भरोसा पक्का करते हैं। जुलाई 2026 में 77,692 मोबाइल बरामद किए गए। इस उपलब्धि की केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने प्रशंसा की है।

नागरिक 'संचार साथी' वेब पोर्टल **www.sancharsaathi.gov.in** या मोबाइल एप के जरिए गुम/चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट कर सकते हैं। शिकायत के बाद मोबाइल को भारतीय दूरसंचार नेटवर्क पर ब्लॉक कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस मोबाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो नेटवर्क इसकी जानकारी दर्ज कर नागरिक और संबंधित पुलिस थाने को भेजता है। इससे पुलिस को मोबाइल बरामद करने और उसे वास्तविक मालिक तक पहुंचाने में मदद मिलती है।

परिवर्तन योजना : दिल्ली-एनसीआर में 1,300 से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत

दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण सुधार और वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से 14 जुलाई, 2026 को शुरू परिवर्तन योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। योजना में 27 अगस्त तक 1,300 से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं, वहीं 42 बैंक और 15 ऑटो ओईएम जुड़ चुके हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में बीएस-**IV** या उससे पुराने मानक वाले 2 लाख से अधिक ट्रक और बसों को बीएस-**VI** या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। योजना पर कुल 9,585 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

परिवर्तन योजना के तहत रोड टैक्स में 10 वर्षों की अवधि के लिए छूट की अधिसूचना संबंधित राज्य पहले ही जारी कर चुके हैं। योजना में डीजल व सीएनजी वाहन खरीदने वालों को ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को एकमुश्त 64 हजार रुपये से 2.56 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

आत्मनिर्भर भारत... नौ सेना को एक हफ्ते में दो स्वदेश निर्मित पोत सौंपे गए

भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौ सेना को अगस्त के अंतिम सप्ताह में दो स्वदेश निर्मित पोत सौंपे गए। नौ सेना बेड़े में शामिल पहला स्वदेशी बहु-उद्देश्यीय पोत 'समर्थक' है। दूसरा निस्तार श्रेणी का डाइविंग सपोर्ट पोत 'आईएनएस निपुण' है। दोनों ही पोत के निर्माण में 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय नौ सेना को पहला स्वदेशी बहु-उद्देशीय पोत 'समर्थक' 27 अगस्त को सौंपा गया। इसे एक बहु-उपयोगी परीक्षण और मूल्यांकन प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया गया है। इस जहाज को समुद्री निगरानी और टोह लेने, अपतटीय गश्त करने और जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत (डीएसवी) आईएनएस निपुण के शामिल होने से नौ सेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी, पानी के भीतर अभियानों और पनडुब्बी बचाव अभियानों की क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है।

पीएम स्वनिधि : पुनर्गठन के बाद 10.56 लाख नए लाभार्थियों को लोन

रेहड़ी-पटरी वालों की सहायता के लिए शुरू पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन कर बीते वर्ष 31 मार्च, 2030 तक विस्तार किया गया। पुनर्गठन के बाद के एक वर्ष में 10.56 लाख नए लाभार्थियों को 6,294 करोड़ रुपये की राशि के 21.86 लाख लोन दिए गए हैं। वहीं पात्र वेंडर के लिए शुरू यूआईपी लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड भी 27 हजार से अधिक जारी किए जा चुके हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 78.68 लाख स्ट्रीट वेंडर को 1.18 करोड़ से अधिक के लोन दिए गए। 421 करोड़ रुपये की ब्याज पर सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन करने वालों को 418 करोड़ रुपये का कैशबैक भी दिया गया है।

भारत सरकार की योजना से बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत 6,844 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाले 31 और नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसे मिलाकर अभी तक 106 ईसीएमएस परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिसमें 69,548 करोड़ रुपये के निवेश और 75 हजार प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। योजना की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तेजी आई है। अभी तक 38 संयंत्र चालू हो चुके हैं जबकि 16 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यह योजना जरूरी घटकों और कच्चे माल के पहली बार घरेलू विनिर्माण के जरिए 'स्वदेशी' मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा दे रही है। ईसीएमएस की क्षमता घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही उससे अधिक उत्पादन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। असल में, एनोड मटेरियल (110%), ऑप्टिकल ट्रांसीवर एसएफपी (350%) और रिले (200%) जैसे अहम क्षेत्रों में उत्पादन पहले ही मांग से ज्यादा हो गया है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति की 53वीं बैठक

गुणवत्ता रफ्तार साथ-साथ

सक्रिय शासन और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाए गए आईसीटी-आधारित, मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन-प्रगति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगरानी करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 25 अगस्त को प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी छह प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की...

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी से सिर्फ लागत ही नहीं बढ़ती, बल्कि नागरिकों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभ में भी देरी हो जाती हैं। सेवा तीर्थ में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अलग-अलग हिस्सों, टुकड़ों या पैकेजों के बजाय एक एकीकृत इकाई के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनकी निगरानी की जानी चाहिए। अलग-अलग पैकेजों में हो रही प्रगति का नतीजा आखिर में संपूर्ण परियोजना के वक्त पर पूरा होने और उसके चालू होने के रूप में निकलना चाहिए। इसलिए मंत्रालयों और राज्यों से कहा गया कि वे काम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा करने का नजरिया अपनाएं और उन कमियों को दूर करें, जिनसे पूरे प्रोजेक्ट के चालू होने और फायदे मिलने में देरी हो सकती है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों में सक्रिय कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देने और परियोजनाओं को लागू करने के लिए हर स्तर पर जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया।

काम तेजी से पूरा करने पर विशेष जोर

पीएम मोदी ने संपर्क को मजबूत करने, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा करते वक्त समय-सीमा का पालन, अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, लंबित मुद्दों के समाधान और काम को तेजी से पूरा करने पर विशेष जोर दिया।

परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हुई हैं और इनकी कुल लागत

30,000

करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रगति की 53 बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 86 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा कर उनकी बाधाएं दूर की।

एआई जैसी नई डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल पर बल

डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कृषि डेटा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए एआई जैसी नई डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि इनपुट प्लानिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक, पूरी कृषि मूल्य श्रृंखला में डेटा इकोसिस्टम का असरदार ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि बेहतर जानकारी के आधार पर कदम उठाए जा सकें। डेटा के आधार पर फैसले लिए जा सकें और सही लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। उन्होंने एग्रीस्टैक व्यवस्था बनाने में राज्यों और केंद्र सरकार की कोशिशों की तारीफ करने के साथ ही किसानों के लिए बेहतर नतीजे पाने के लिए इसके इस्तेमाल को और मजबूत करने का आह्वान किया।

साइबर धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रशिक्षण, जागरूकता और शिक्षा पर लगातार ध्यान देकर ऐसे मामलों की रोकथाम को मजबूत किया जाना चाहिए। साइबर धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं भी शामिल थी। उन्होंने लगातार और खासतौर पर बुजुर्गों, युवाओं एवं कमजोर वर्गों के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को धोखाधड़ी के तरीकों, चेतावनी के संकेतों और सुरक्षित डिजिटल तौर-तरीकों के बारे में जानकारी इन अभियानों में दी जाए। उन्होंने इससे जुड़े कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित ट्रेनिंग की भी बात कही, ताकि साइबर धोखाधड़ी के नए तरीकों की पहचान की जा सके।

> *"काम को तेजी से पूरा करने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।"*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

कतार से क्यूआर कोड तक

नए भारत की यूपीआई भुगतान क्रांति

बटुए से निकलते नोट, गल्ले में गिनकर रखे गए सिक्के और एटीएम की कतार-यह सब अब भारत की एक पुरानी याद भर रह गए हैं।एक क्यूआर कोड, एक स्कैन और चंद सेकंड-आज देश के लेनदेन की यही नई भाषा है। दस वर्ष पहले 25 अगस्त को एक परिवर्तनकारी शुरुआत हुई थी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली बनकर भारत की पहचान बन चुकी है। यह कहानी है उस बदलाव की, जिसने रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर बड़े व्यापारी तक, देश से लेकर विदेश तक, लोगों के जीवन को बनाया सुगम...

मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी को साइकिल चाची के नाम से जाना जाता है। वह अचार बनाने का काम करती हैं और साइकिल पर उसे बेचने निकल पड़ती हैं। वह बताती हैं कि लोग खुदरा नहीं है कह कर 40-50 रुपये कम देते थे। कहते थे कि बाद में दे देंगे लेकिन भूल जाते थे। वो कहती हैं कि हमें मुनाफा ही नहीं होता था लेकिन अब यूपीआई के आने से ऐसा नहीं होता है। जबसे यूपीआई से पैसा लेना शुरू किया कारोबार में और बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई ने उनके व्यवसाय को न सिर्फ नई गति दी बल्कि सहज डिजिटल भुगतान ने हर लेनदेन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाया है।

एक अन्य महिला जिन्हें बैंक से रुपये निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ता था अब यूपीआई के आने से काफी खुश हैं। वह बताती हैं कि पहले हमें दो-दो घंटा रुपये निकालने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम बिना पैसा निकाले वापस लौट जाते थे। अब यूपीआई आने के बाद हम आसानी से ही घर बैठे लेनदेन कर सकते हैं।

यह कहानी सिर्फ मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी की नहीं है बल्कि देश में ऐसे लाखों रेहड़ी-पटरी वाले या छोटे कारोबारी हैं, जिनकी दुकान का काउंटर आज एक क्यूआर कोड से सज चुका है। यही वह जमीनी सच्चाई है, जो बताती है कि यूपीआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की कहानी है।

यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में यूपीआई ने देश के कोने-कोने तक अपनी व्यापक पहुंच बनाते हुए डिजिटल भुगतान को आम नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। यूपीआई की गौरवपूर्ण यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा कि इसकी उपलब्धियों पर हर भारतीय गर्व कर सकता है।

वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (यूपीआई) की शुरुआत की, जिसने

यूपीआई का परिवर्तनकारी दशक

- वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए लगभग दो करोड़ लेनदेन हुए थे और उनका कुल मूल्य मुश्किल से सात हजार करोड़ रुपये के आसपास था। दस साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई मंच पर चौबीस हजार करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज हुए, जिनकी कुल कीमत 314.23 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही। यानी लेनदेन की संख्या में करीब बारह हजार गुना और मूल्य में चार हजार गुना से ज्यादा की छलांग।

- संसद में हाल ही में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 तक यूपीआई मंच 55.5 करोड़ व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा देता है। 740 से अधिक बैंक जिनमें सरकारी, निजी, लघु वित्त, भुगतान और सहकारी, सब इस एक मंच पर आपस में जुड़े हैं। यही वह इंटरऑपरेबिलिटी है जिसकी तारीफ करते आईएमएफ के विशेषज्ञ नहीं थकते। किसी एक एप या बैंक तक सीमित न रहकर, हर प्रणाली को हर दूसरी प्रणाली से जोड़ देने की सोच इसमें शामिल है।

पिछले पांच वित्त वर्षों में यूपीआई लेनदेन की रफ्तार-मात्रा और मूल्य, दोनों में लगातार तेजी

वित्त वर्ष	लेनदेन (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ रुपये में)
2021-22	4,595.61	84.16
2022-23	8,371.44	139.15
2023-24	13,112.95	199.95
2024-25	18,586.60	260.56
2025-26	24,161.69	314.23

मासिक रिकॉर्ड : मार्च 2026 में एक ही महीने में 2,264 करोड़ लेनदेन दर्ज हुए, जिनकी कीमत 29.53 लाख करोड़ रुपये रही।

स्रोत : वित्त मंत्रालय, लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़े (जून 2026)

भारत में पैसों के लेनदेन को बेहद आसान बना दिया। इसके जरिए बिना खाता संख्या या आईएफएससी कोड साझा किए, केवल एक मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और सुरक्षित पिन की मदद से तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। 24×7 काम करने वाली यह प्रणाली विभिन्न बैंकों और एप के बीच रियल-टाइम में काम करती है। सभी बैंकों के बीच आपसी तालमेल और कम लागत की वजह से इसका विस्तार तेजी से हुआ है। अप्रैल 2016 में जहां इससे 21 बैंक जुड़े थे, वहीं अगस्त 2026 तक यह संख्या बढ़कर 741 हो गई है। यूपीआई ने केवल भुगतान को ही आसान नहीं बनाया, बल्कि वित्तीय समावेशन को भी नई दिशा दी है। नकदी पर निर्भरता में कमी आई। त्वरित लेनदेन ने नकदी की जरूरत को घटाया और पारदर्शिता बढ़ाई है। यूपीआई की अंतिम छोर तक पहुंच ने जीवन

55.49+ करोड़ लोग **6.5** करोड़ व्यापारी हैं उपयोगकर्ता (जून 2026)

741 जुड़े हुए बैंक

85% भारत के डिजिटल भुगतान में हिस्सेदारी

50% दुनिया के रियल टाइम पेमेंट में यूपीआई की भागीदारी

यूपीआई : एक दशक के मील के पत्थर

2016	11 अप्रैल को मुंबई में तत्कालीन आरबीआई गवर्नर द्वारा यूपीआई का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च।
2016-17	25 अगस्त 2016 को यूपीआई आमजन के लिए शुरू। पहले वर्ष में हुआ लगभग दो करोड़ का लेनदेन।
2019	पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक ऋण और डिजिटल भुगतान से जोड़ने की पहल तेज हुई।
2021-22	वार्षिक लेनदेन साढ़े चार हजार करोड़ के पार, यूपीआई शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचा।
2023	फ्रांस में एफिल टॉवर सहित कई स्थानों पर यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू।
2025	अगस्त में मासिक लेनदेन पहली बार दो हजार करोड़ के पार, आईएमएफ ने यूपीआई को वैश्विक मिसाल बताया।
2025-26	वार्षिक लेनदेन चौबीस हजार करोड़ के पार, मूल्य 314 लाख करोड़ रुपये से अधिक।
2026	संसद ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन पारित किया, उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा।

को बहुत आसान बना दिया है।

ऑटो चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, ग्रामीण मंडियों के किसान और घरेलू कामगार अब आसानी से क्यूआर कोड और स्मार्टफोन से लेनदेन कर रहे हैं, जिससे शहरी-ग्रामीण और औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्र की दूरी खत्म हुई है। औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने के कारण छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र

> *यूपीआई का हमारा अपना प्लेटफॉर्म आज दुनिया के लिए अजूबा बन चुका है, अकेला भारत रियल टाइम लेनदेन में आधी हिस्सेदारी रखता है।*
>
> ***-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री***

रेहड़ी-पटरी से मॉल तक: हर हाथ में यूपीआई

यूपीआई की असली ताकत उसके आंकड़ों में उतनी नहीं, जितनी उसकी पहुंच में है। कुल लेनदेन में से 63% हिस्सा व्यक्ति से व्यापारी यानी पी2एम भुगतान का है। इसमें भी 86% लेनदेन 500 रुपये से कम राशि के हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूपीआई अब सिर्फ बड़े शहरों की सुविधा नहीं रह गया है। यह सब्जी वाले, चाय वाले, ऑटो रिक्शा चालक और गली-मोहल्ले की छोटी दुकान तक पहुंच चुका है। ऑटो रिक्शा चालक हो या रेहड़ी-पटरी वाला, अब किसी को भी सवारी या ग्राहक से 'छुट्टे पैसे' को लेकर उलझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यूआर कोड का एक स्कैन ही काफी है।

- पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक ऋण से जोड़े जाने के बाद यह वर्ग भी अब बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। जो कारोबारी कभी नकद लेनदेन तक सीमित था, वह आज यूपीआई के जरिए अपना डिजिटल लेनदेन का इतिहास बना रहा है। यही इतिहास आगे चलकर उसे बिना गारंटी के छोटे कर्ज दिलाने में मददगार साबित हो रहा है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे 'सभी के लिए मंच, सभी के लिए प्रगति' के सिद्धांत के रूप में बार-बार रेखांकित करते हैं। वह कहते हैं कि आधार, डिजिलॉकर, ओएनडीसी और यूपीआई जैसे खुले डिजिटल मंचों ने भारत को एक ऐसा सार्वजनिक ढांचा दिया है, जिसमें मॉल में खरीदारी करने वाला ग्राहक और सड़क किनारे ठेला लगाने वाला विक्रेता, दोनों एक ही सुविधा का लाभ उठाते हैं।

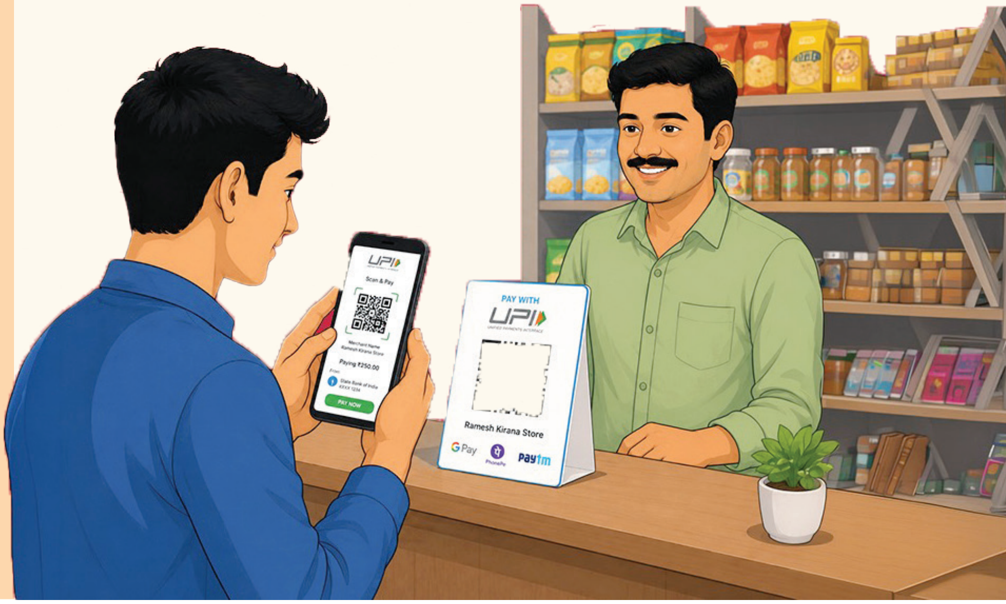

आज पीएम स्वनिधि से जुड़ा रेहड़ी-पटरी वाला भी यूपीआई से लेनदेन करता है। यही समावेशी भारत की असली तस्वीर है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

के कामगारों के लिए ऋण और बचत के नए रास्ते खुले हैं। आज यूपीआई एक व्यापक वित्तीय मंच बन चुका है। छोटे भुगतानों के लिए 'यूपीआई लाइट', बिल व सब्सक्रिप्शन के लिए 'यूपीआई ऑटो-पे' और पूर्व-स्वीकृत ऋण सीमाओं के लिए 'यूपीआई पर क्रेडिट' जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मजबूत ढांचे के आधार पर बैंक और फिनटेक कंपनियां लोगों की जरूरतों के अनुसार

तीन स्तंभों पर टिकी है बुनियाद

इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड (आईएमएफ) के विशेषज्ञ जब यूपीआई की सफलता का विश्लेषण करते हैं, तो वे अकेले यूपीआई की बात नहीं करते। वे इसे भारत के व्यापक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई मॉडल का नतीजा मानते हैं, जिसकी बुनियाद तीन स्तंभों पर टिकी है। जन धन, आधार और मोबाइल। सरकार इसे संक्षेप में 'जेएएम ट्रिनिटी' कहती है...

जन धन

करोड़ों नागरिकों के बैंक खाते खोलकर हर परिवार को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा।

59 करोड़ से अधिक जनधन खाते, 26 अगस्त, 2026 तक।

आधार

हर भारतीय को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान मिली, जिसने खाता खोलने और सत्यापन को सरल बनाया।

145 करोड़ आधार नंबर, जुलाई, 2026 तक जारी किए।

मोबाइल

दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल डेटा ने हर हाथ को इंटरनेट और भुगतान मंच से जोड़ दिया।

120 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन यूजर, जुलाई, 2026 तक।

इन तीनों नींव के पत्थरों पर जब भुगतान की परत चढ़ी, तो यूपीआई का जन्म हुआ। आईएमएफ का मानना है कि नकदी पर निर्भर बाकी देश भी इसी तरह पहचान, खाता, कनेक्टिविटी और फिर भुगतान को अपनाकर अपने यहां वित्तीय समावेशन की रफ्तार बढ़ा सकते हैं।

वित्तीय उत्पाद देश के कोने-कोने तक पहुंचा रही हैं।

यूपीआई और आम नागरिक का भरोसा

बिहार के मुजफ्फरपुर की राजकुमारी सिर्फ अकेली महिला नहीं हैं ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनका जीवन और कारोबार यूपीआई ने आसान किया है। दिल्ली की किसी गली में चाट की दुकान पर भीड़ लगी हो या किसी गांव की परचून दुकान पर, दृश्य अब एक जैसा है। ग्राहक मोबाइल निकालता है, भुगतान चंद पलों में पूरा हो जाता है और दुकान पर रखा साउंड बॉक्स बोल उठता है। न बटुआ निकालने की जल्दी, न छुट्टे को लेकर झिकझिक। यह सहजता यूं ही नहीं आई। इसके पीछे एक सोची-समझी नीति, एक तकनीकी क्रांति और

क्यों यूपीआई है यूनिक...

- मोबाइल फोन के जरिए 24×7 और 365 दिन तत्काल धन हस्तांतरण।
- एक ही एप्लिकेशन से कई बैंक खातों तक पहुंच।
- दो-स्तरीय प्रमाणीकरण, यानी सुरक्षा और सुगमता दोनों साथ-साथ।
- वर्चुअल पते की सुविधा-खाता संख्या या कार्ड विवरण साझा करने की जरूरत नहीं।
- क्यूआर कोड और इंटेंट आधारित भुगतान की सुविधा।
- कैश ऑन डिलीवरी और खुले पैसों के झंझट से मुक्ति।
- व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम), दोनों तरह के भुगतान एक ही मंच पर।
- मोबाइल एप से सीधे शिकायत दर्ज कराने और निवारण की सुविधा।

भारतीय इनोवेशन की वैश्विक स्वीकार्यता

- जून 2025 में आईएमएफ ने एक फिनटेक नोट प्रकाशित किया, जिसका विषय था बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतानों में इंटरऑपरेबिलिटी की भूमिका। इसमें कहा गया कि 2016 में शुरू हुई भारत की यह भुगतान व्यवस्था पूरे डिजिटल भुगतान परिदृश्य के लिए एक मिसाल बन गई है। कुछ महीनों बाद, सितंबर 2025 में आईएमएफ की अपनी पत्रिका 'फाइनांस एंड डेवलपमेंट' ने भारत के निर्बाध भुगतान तंत्र पर विस्तृत लेख प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया कि यूपीआई अब दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन चुकी है, जिसके जरिए हर महीने औसतन उन्नीस अरब से अधिक लेनदेन होते हैं।
- यह प्रशंसा किसी संयोग का नतीजा नहीं है। दशकों तक वैश्विक वित्तीय ढांचे पर पश्चिमी संस्थाओं और कार्ड नेटवर्कों का दबदबा रहा। पहली बार किसी विकासशील देश का सार्वजनिक डिजिटल मंच दुनिया के सामने एक निर्यात योग्य मॉडल के रूप में खड़ा हुआ है। यह बदलाव भले शोर-शराबे के बीच न हुआ हो, लेकिन इसकी गूंज गहरी है। यह सिर्फ पैसों की आवाजाही भर नहीं, बल्कि नवाचार, समावेशन और भरोसे को लेकर भारत की साख की भी कहानी है।

> एक दशक पहले शुरू हुआ यूपीआई ने देश में डिजिटल लेनदेन को सरल, तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हुए भुगतान के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव ला दिया है।
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

करोड़ों भारतीयों का भरोसा जुड़ा है, जिसका नाम है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। इसी भरोसे की वजह से हर सेकेंड में न सिर्फ 1 करोड़ यूपीआई पेमेंट भारत में हो रहे हैं बल्कि हर 2 में से 1 ग्लोबल यूपीआई पेमेंट भारत में किया जा रहा है। इसके लिए देश में 81 करोड़ से अधिक यूपीआई पेमेंट प्वाइंट भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं।

दुनिया को राह दिखाता भारत का यूपीआई मॉडल

जो प्रयोग कभी मुंबई की एक शाखा तक सीमित था, वह आज दुनिया के कई देशों में अपनी धाक जमा रहा है। सिंगापुर में यूपीआई को वहां की भुगतान व्यवस्था 'पेनाउ' से जोड़ा गया है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा-पार धन हस्तांतरण चंद पलों में संभव हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात और मॉरीशस में भारतीय पर्यटक अब स्थानीय दुकानों में यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। फ्रांस में तो पेरिस के मशहूर एफिल टॉवर पर भी अब भारतीय सैलानी सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन कर रुपये में अपना बिल चुका सकते हैं।

नेपाल, भूटान और श्रीलंका में यूपीआई पहले से स्वीकार्य है, जबकि कतर, ग्रीस और कंबोडिया में स्थानीय भागीदार संस्थाओं के साथ मिलकर इसका विस्तार किया जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई केंद्रीय बैंकों और फिनटेक कंपनियों से भी बातचीत जारी है। कुल मिलाकर आज एक दर्जन से अधिक देशों में यूपीआई आधारित भुगतान सुविधा किसी न किसी रूप में उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी ने भारत के इनोवेशन को दी नई ताकत

- **सिंगापुर** : 'पेनाउ' के साथ एकीकृत, सीमा-पार तात्कालिक हस्तांतरण।
- **संयुक्त अरब अमीरात** : प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर स्वीकार्य, भारतीय प्रवासियों में लोकप्रिय।
- **फ्रांस** : भारतीय पर्यटकों के लिए एफिल टॉवर सहित कई जगह भुगतान सुविधा।
- **भूटान व नेपाल** : देशभर में स्वीकार्यता, एनपीसीआई-सक्षम रियल-टाइम क्रॉस-बॉर्डर व्यवस्था।
- **श्रीलंका व मॉरीशस** : स्थानीय भुगतान ढांचे के साथ एकीकरण।
- **कतर, ग्रीस व कंबोडिया** : स्थानीय बैंकों के साथ भागीदारी में विस्तार जारी।
- **उज्बेकिस्तान: यूपीआई के लिए 20 अगस्त 2026 को समझौता।**

यही वजह है कि आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जैसी वैश्विक संस्था के अर्थशास्त्री भी यूपीआई की सफलता को बारीकी से समझने में जुटे हैं। जो देश दशकों तक नकदी पर निर्भर रहा, वह आज डिजिटल भुगतान की क्रांति में बाकी दुनिया को राह दिखा रहा है।

जानिए: यूपीआई है क्या?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक ऐसी व्यवस्था है, जो एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए कई बैंक खातों को आपस में जोड़ देती है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक वर्चुअल पते या क्यूआर कोड की मदद से, बिना खाता संख्या और आईएफएससी कोड याद रखे, चौबीसों घंटे और साल के 365 दिन तत्काल पैसा भेज

संसद से पारित नया कानून

अगस्त 2026 में संसद के दोनों सदनों ने 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' को मंजूरी दी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। इस विधेयक का एक अहम हिस्सा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन से जुड़ा है। इसी वजह से यूपीआई को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई।

कानून की मुख्य बातें आसान भाषा में समझिए...

- यह संशोधन भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में किया गया है, जिससे पहले बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को यूपीआई जैसे अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर वसूलने से रोका गया था।
- संशोधन के बाद सरकार को भविष्य में अधिसूचना जारी कर बैंकों व भुगतान सेवा प्रदाताओं को कुछ चुनिंदा श्रेणियों के व्यापारिक लेनदेन पर सेवा शुल्क तय करने का अधिकार मिलेगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ता के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त बना रहेगा, जैसा कि यह शुरुआत से रहा है, किसी भी सामान्य नागरिक को यूपीआई से भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- संभावित शुल्क केवल कुछ बड़े और चुनिंदा व्यापारिक श्रेणियों के लेनदेन पर लागू होने की बात कही गई है। इसका ब्यौरा भविष्य में अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- यह विधेयक कराधान से जुड़े कई अन्य विषयों को भी समेटे है, जैसे विदेशी निवेश को सुगम बनाना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन और कच्चे हीरे के व्यापार में राहत।
- सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद यूपीआई की सफलता को बनाए रखते हुए भुगतान तंत्र को और मजबूत एवं टिकाऊ बनाना है, ताकि बैंकों तथा सेवा प्रदाताओं को इस विशाल ढांचे के रखरखाव के लिए संसाधन मिलते रहें।

या मंगवा सकता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) संचालित करता है।

मुंबई से शुरू हुआ था यूपीआई का सफर

11 अप्रैल 2016 का दिन भारत के डिजिटल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन मुंबई में तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था। शुरुआत में यह मुट्ठी भर बैंकों और चुनिंदा ग्राहकों तक सीमित एक प्रयोग भर था। 25 अगस्त को आमजन के लिए शुरू हुआ। किसी ने शायद ही अंदाजा लगाया होगा कि आने वाले दशक में यही मंच देश के हर कोने में, हर हाथ में मौजूद मोबाइल फोन के भीतर बस जाएगा।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने

सुरक्षा की मजबूत चौकसी

जैसे-जैसे यूपीआई का दायरा बढ़ा है, वैसे-वैसे उसकी सुरक्षा को लेकर भी उतनी ही गंभीरता बरती गई है। सरकार, रिजर्व बैंक और एनपीसीआई ने मिलकर धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम-आधारित लेनदेन की सीमाएं तय की हैं। मोबाइल नंबर में अनधिकृत बदलाव और एसएमएस आधारित सत्यापन के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। एनपीसीआई ने हाल ही में व्यापक यूपीआई सूचना सुरक्षा ढांचा और मोबाइल एप्लिकेशन सुरक्षा ढांचा भी जारी किया है, ताकि करोड़ों उपयोगकर्ताओं का भरोसा बना रहे।

सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान...

- रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 में जारी निर्देश के तहत 1 अप्रैल 2026 से यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट सहित सभी डिजिटल भुगतानों के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) अनिवार्य कर दिया है।
- अब हर लेनदेन को कम से कम दो अलग-अलग और स्वतंत्र तरीकों से सत्यापित करना जरूरी है, जैसे पिन, पासवर्ड, ओटीपी या बायोमेट्रिक पहचान में से कोई दो।
- यह कदम फिशिंग और सिम-स्वैप जैसी धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है, जहां अकेले ओटीपी आधारित सत्यापन असुरक्षित साबित हो रहा था।

- रिजर्व बैंक का मकसद साफ है, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़कर अनधिकृत लेनदेन खत्म करना और डिजिटल भुगतान प्रणाली में जनता का भरोसा और मजबूत करना।

रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को खड़ा किया। इसका सबसे बड़ा कमाल यह रहा कि इसने अलग-अलग बैंकों के खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए आपस में जोड़ दिया। न कार्ड नंबर याद रखने की जरूरत, न खाता संख्या और न ही आईएफएससी कोड टाइप करने का झंझट। बस एक वर्चुअल पता, एक क्यूआर कोड और पैसा एक खाते से दूसरे खाते में पलक झपकते पहुंच जाता है। यही नहीं अब तो देश में बिना इंटरनेट के भी यूपीआई का उपयोग हो रहा है। UPI 123PAY का उपयोग करके UPI भुगतान के लिए आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात पर गर्व जताते रहे हैं कि दुनिया के कुल रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों में से लगभग आधा हिस्सा अकेला भारत यूपीआई के जरिए संभालता है। उनके शब्दों

यूपीआई सिर्फ भुगतान नहीं नवाचार का नया चेहरा

यूपीआई की यह यात्रा यहीं नहीं थमती। सरकार का इरादा साफ है, नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को जोड़ते हुए अगले दस वर्षों में इनोवेशन के नए आयाम गढ़ना। बीते साल भर में ही यूपीआई ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगस्त 2025 में पहली बार मासिक लेनदेन दो हजार करोड़ के पार पहुंचा, तो दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा और आगे बढ़ गया। पूरे 2025 में औसतन हर दिन 60 करोड़ लेनदेन दर्ज हुए।

> “गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर, आपकी गाड़ी के शो रूम तक, सारी पेमेंट्स, सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है। कई बार तो आपकी बिटिया क्यूआर शेयर कर देती है कि 'पापा-मां मैंने ये ड्रेस ले ली है।' आप घर बैठे-बैठे उसकी शॉपिंग करवा देते हैं। ये चीजें Remarkable हैं। आप सोचिए, 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थीं?
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

दिल्ली की सड़क पर अपना ठेला लगाने वाला विक्रेता, जो अपने साउंड बॉक्स पर बजती भुगतान की आवाज सुनता है, शायद यह न जानता हो कि उसकी यह छोटी-सी सुविधा आईएमएफ जैसी वैश्विक संस्था की नजर में एक मिसाल बन चुकी है। लेकिन उसका रोजमर्रा का भरोसा, तेज, सुरक्षित और बिना नकदी का लेनदेन ही वह असली ताकत है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। यूपीआई अब सिर्फ भुगतान का जरिया नहीं रहा, यह भारत के नवाचार का चेहरा है, समावेशी विकास का प्रतीक है। नकदी से डिजिटल की ओर बढ़ने का सपना देख रहे तमाम देशों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार करने वाला भारत अब क्यूआर कोड के एक स्कैन में अपना काम पूरा कर लेता है। यही है नए भारत की भुगतान क्रांति सरल, सुरक्षित और सबके लिए सुलभ।

में यह महज एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने पिछले एक दशक में भारत के वित्तीय परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यूपीआई

यूपीआई का सफर...

- **2016** : अप्रैल 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था।

- **25 अगस्त 2016** : आम जनता के लिए आरंभ किया गया। बैंकों ने अपने यूपीआई-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिए थे।

- **भीम एप्लिकेशन** : दिसंबर 2016 में यूपीआई का उपयोग करके डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया।

- **डायनेमिक क्यूआर** : 2017 में शुरू हुआ एक रिटेल मर्चेंट प्लेटफॉर्म है, जो डायनेमिक क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाता है। इसमें भुगतानकर्ता की जानकारी और सटीक योगफल शामिल होता है, मैन्युअल राशि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती।

- वर्ष 2018 में डिजिटल भुगतान को सरल, अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ यूपीआई 2.0 लागू किया गया।

- वर्ष 2019 में सेबी ने रिटेल व्यक्तिगत निवेशकों को आईपीओ के लिए आवेदन करते समय पेमेंट के एक विकल्प के तौर पर यूपीआई का इस्तेमाल करने की अनुमति दी।
- अक्टूबर 2019 में यूपीआई ने एक महीने में एक अरब लेनदेन की उपलब्धि हासिल की, जो देश भर में इसके तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है।
- सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल, बीमा प्रीमियम, एसआईपी और ईएमआई के लिए आवर्ती ई-भुगतान को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई ऑटोपे लॉन्च किया गया।

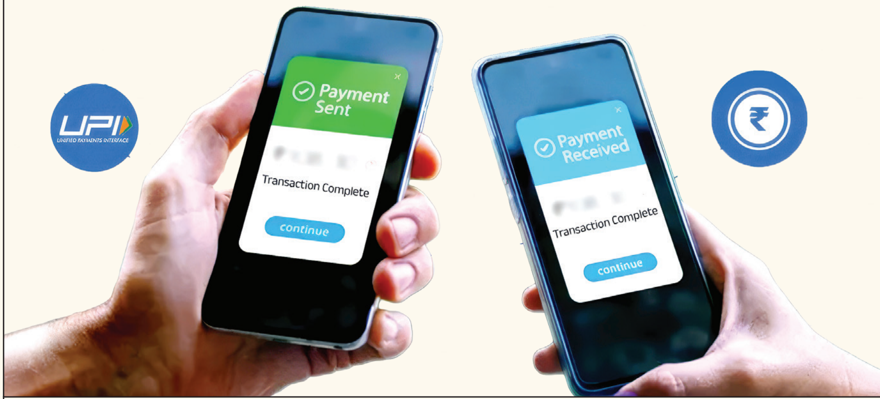

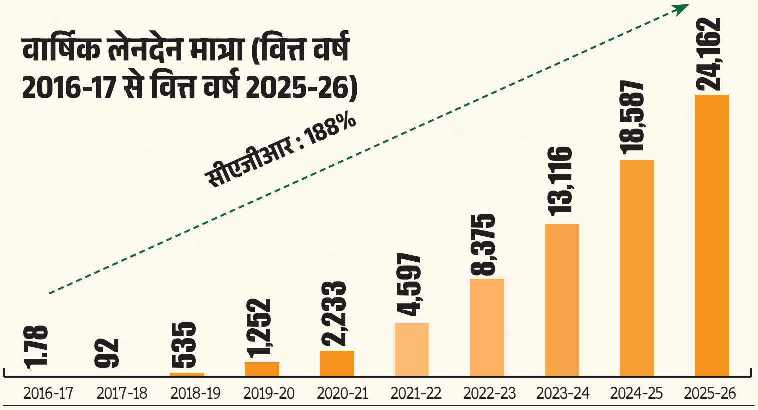

नोट : यूपीआई की वार्षिक लेनदेन मात्रा (करोड़ में)

के जरिए होने वाले लेनदेन की संख्या में लगभग 13 हजार गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के माध्यम से केवल 1 करोड़ 78 लाख लेनदेन हुए थे, वहीं 2025-26 तक यह आंकड़ा अभूतपूर्व उछाल के साथ 24,162 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया। लेनदेन की संख्या के साथ-साथ इसके कुल मूल्य में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसी अवधि के दौरान यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य 7 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपये के विशाल स्तर पर पहुंच गया है। यह असाधारण प्रगति दर्शाती है कि यूपीआई अब केवल तकनीकी विकल्प न रहकर भारत के आम जनजीवन, छोटे व्यापारियों और

यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन की गई

- फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई 123पे के लॉन्च के माध्यम से डिजिटल भुगतान के इकोसिस्टम में शामिल किया गया। यह इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (आईवीआर) नंबर, एप-आधारित कार्यक्षमता, मिस्ड कॉल-आधारित दृष्टिकोण और निकटता ध्वनि-आधारित भुगतान के माध्यम से लेनदेन की अनुमति देता है।
- क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ एकीकृत करने से उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान के विकल्प और भी बढ़ गए।
- वर्ष 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन की शुरुआत की गई।
- वर्ष 2024 में यूपीआई सर्कल की शुरुआत की गई, जिससे प्राथमिक उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते पर पूर्वनिर्धारित लेनदेन सीमाओं के साथ द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को अधिकृत कर सकते हैं।
- वर्ष 2024 में आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी है।
- यूपीआई 123पे के लिए प्रति लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।
- यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है, जबकि प्रति लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है।
- वर्ष 2025 में यूपीआई के लिए ऑन-डिवाइस प्रमाणीकरण शुरू किया गया, जिससे स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के माध्यम से भुगतान करना संभव हुआ।

वार्षिक लेनदेन मूल्य (वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2025-26)

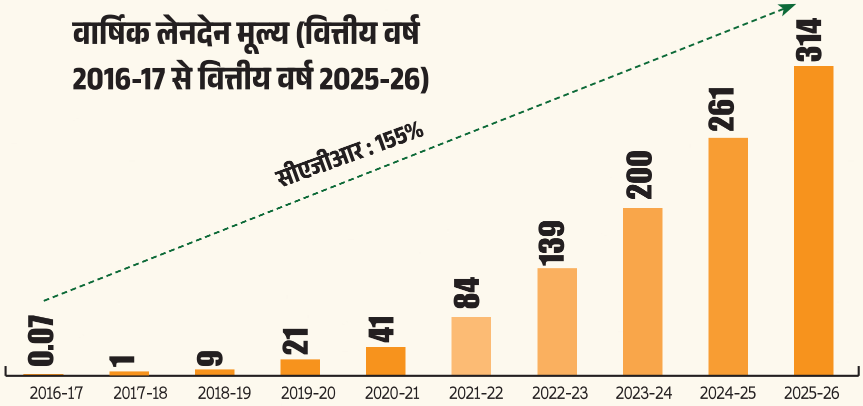

नोट : यूपीआई का वार्षिक लेनदेन मूल्य (लाख करोड़ रुपये में)

बड़े व्यवसायों के दैनिक वित्तीय लेनदेन की रीढ़ बन चुका है। आसान यूजर इंटरफेस, तत्काल भुगतान की सुविधा, शून्य प्रत्यक्ष लागत और व्यापक डिजिटल कनेक्टिविटी ने देश के दूर-दराज इलाकों तक वित्तीय समावेशन को तेजी से पहुंचाया है। सब्जी के ठेले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक क्यूआर कोड की मौजूदगी ने नकदी पर निर्भरता को बेहद कम किया है। यूपीआई की यह तीव्र वृद्धि न केवल भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की मजबूती का प्रमाण है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

चार मल्टीट्रैकिंग

एक हाइवे परियोजना को मंजूरी

राष्ट्र के विकास के लिए जहां नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 19 अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार लेन में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी...

" *बिहार के चौतरफा विकास के हमारे प्रयासों में कनेक्टिविटी का तेज विस्तार बहुत जरूरी है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने NH-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा सेक्शन पर 4-लेन के निर्माण को मंजूरी दी है। पूरे राज्य के लिए लाइफलाइन साबित होने वाली इस परियोजना से प्रगति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इससे जहां सफर में लगने वाला समय बचेगा, वहीं आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।* **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

निर्णय : बिहार में एनएच-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार- लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति।

प्रभाव :

- इस परियोजना का विकास हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत किया जाएगा और इसकी कुल लागत 3,590.73 करोड़ रुपये होगी।
- परियोजना से मुजफ्फरपुर, मुक्सुदपुर, रुन्नी सैदपुर, थुम्मा, ढुमरा, भुतही और सोनबरसा के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी।
- परियोजना से यात्रियों और माल की तेज और सुरक्षित आवाजाही, यात्रा दक्षता में सुधार और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
- बेहतर कनेक्टिविटी से बौद्ध सर्किट और सीतामढ़ी स्थित ऐतिहासिक जानकी पुनौरा धाम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध होगी।

निर्णय : पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को कवर करने वाली रेलवे की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी।

प्रभाव : बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। इन बहु-ट्रैकिंग परियोजनाओं से परिचालन के सुव्यवस्थित होने और भीड़भाड़ में कमी आने की उम्मीद है।

- इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इससे लगभग 6,448 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 60 लाख है।
- परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये है, जिन्हें 2030-31 तक पूरा किया जाना है।

इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

1. खड़गपुर - भद्रक (रानीताल) चौथी लाइन - 173 किमी (पश्चिम बंगाल और ओडिशा)
2. भद्रक - हरिदासपुर चौथी लाइन - 75 किमी (ओडिशा)
3. गुम्मिडिपुंडी - गुडुर तीसरी और चौथी लाइन - 90 किमी (आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु)
4. डी. कटक - पारादीप (बडाबंधा) तीसरी और चौथी लाइन - 72 किमी (ओडिशा)

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

स्वास्थ्य सुरक्षा की ऐतिहासिक क्रांति

'आयुष्मान भारत'

स्वस्थ-सशक्त होता नया भारत

'आयुष्मान भारत योजना' आज देश के करोड़ों परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। 23 सितंबर 2018 से शुरू हुई इस योजना के तहत देश के 60 करोड़ से अधिक नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की गारंटी मिल रही है। अब तक 47 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं और 11 करोड़ से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज देकर लाभार्थी परिवारों को आर्थिक संकट से उबारा गया है। हर नागरिक तक बेहतर इलाज पहुंचाकर यह योजना 'स्वस्थ और समृद्ध भारत' का सपना कर रही है साकार...

एक दौर था जब बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं, पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ को तोड़ देती थी। अस्पताल की चौखट पर खड़े गरीब को इलाज के लिए अपनी जमीन और गहने गिरवी रखने पड़ते थे। लेकिन बीते वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। 'आयुष्मान भारत' योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के करोड़ों निर्धन और वंचित परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी बनी है।

यह एक ऐसी पहल थी जिसने भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन किया और लोगों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके कारण भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में क्रांति का साक्षी बन रहा है। इस योजना ने लाभार्थियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

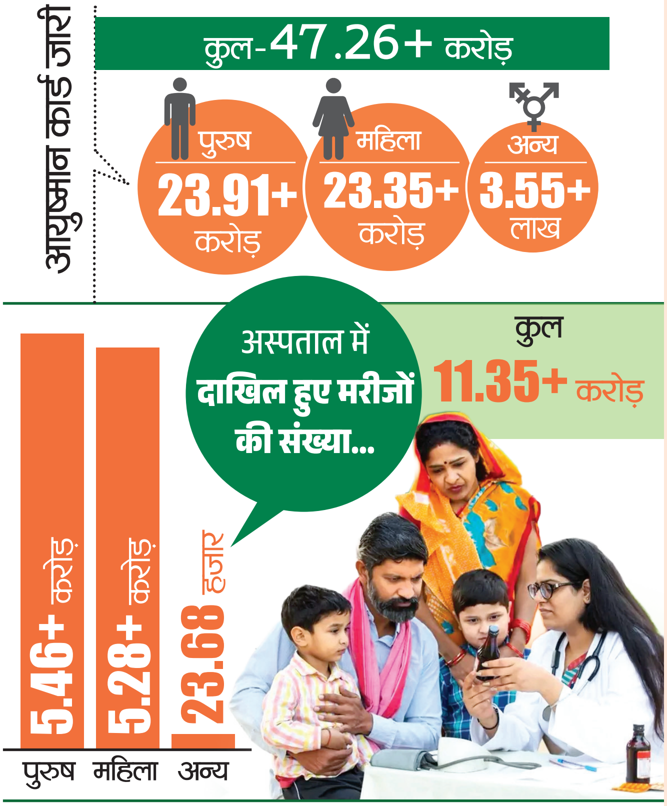

पंजीकृत अस्पताल

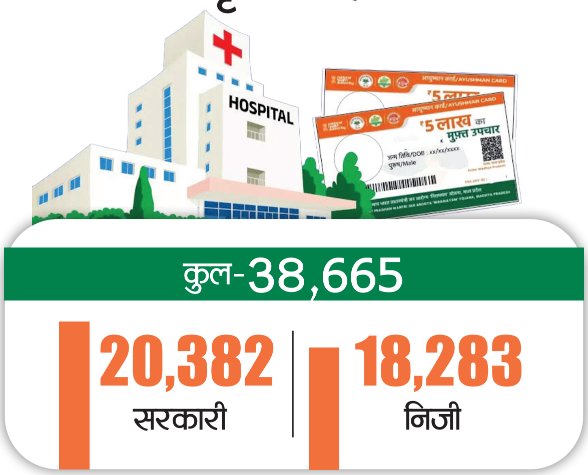

एबी-पीएमजय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य...

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड से हुई थी।
- इस योजना ने स्वास्थ्य बीमा पर सरकारी खर्च बढ़ाकर परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करने में मदद की है। परिवारों को 2024-2025 में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई।
- एबी-पीएमजेएवाई के लिए बजट अनुमान 2026-27 में बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये किया गया जो वित्त वर्ष-2025-26 की तुलना में 500 करोड़ रुपये ज्यादा है।
- योजना के तहत द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
- मार्च 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया गया।
- अक्टूबर 2024 में योजना का और विस्तार करते हुए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, जो 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना योजना के दायरे में शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय का अनुपात 2014-15 के 62.6 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 43.4 प्रतिशत रह गया है।

गंभीर बीमारियों के इलाज से लेकर आधुनिक सर्जरी तक, 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार ने आम नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। देश भर के हजारों निजी और सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों में तकनीक और पारदर्शिता के संगम से आज गांव-कस्बों के लोग भी बड़े निजी और सरकारी अस्पतालों में बिना एक भी पैसा खर्च किए उच्चस्तरीय इलाज पा रहे हैं। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी इस सुरक्षा चक्र में जोड़कर योजना ने संवेदनशीलता की नई मिसाल पेश की है। 'आयुष्मान भारत' ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति में जन-कल्याण और नीयत में निष्ठा हो, तो हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सकता है। ■

पोषित भारत स्वस्थ भारत

सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव पोषित और स्वस्थ नागरिकों पर टिकी है। इसी संकल्प के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर वर्ष सितंबर को 'राष्ट्रीय पोषण माह' के रूप में मनाता है। जन-आंदोलन के तौर पर मनाए जाने वाले 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की थीम "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" रखी गई है। यह राष्ट्रीय अभियान केवल पोषण वितरण तक सीमित नहीं बल्कि माताओं के सशक्तीकरण को सामुदायिक स्वामित्व के साथ जोड़कर एक स्वस्थ और समर्थ भारत की राह कर रहा है प्रशस्त...

भारत में कुपोषण उन्मूलन और समग्र स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में पोषण अभियान एक जन-आंदोलन सिद्ध हुआ है। मार्च 2018 में शुरू इस अभियान के तहत इस वर्ष 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ 9 सितंबर 2026 को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया जो अगले एक महीने तक चलेगा।

आहार में केवल कैलोरी की पूर्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व और खाद्य विविधता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सामुदायिक सहभागिता से युक्त बनाया गया है। इसमें गर्म पकाए गए भोजन के मानक तय किए गए हैं। आंगनवाड़ी स्तर पर पारदर्शिता के लिए 'एसएनपी मेन्यू

पोषण माह 2026

5 प्रमुख प्राथमिकताएं...

1 आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन

विविध व्यंजनों का प्रदर्शन: स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाजों, मोटे अनाज (मिलेट्स), दाल, मौसमी फल, सब्जी, तिलहन, दूध और अंडों के उपयोग से पौष्टिक व्यंजन बनाने का प्रदर्शन।

पोषण मेला एवं प्रतियोगिताएं: पोषक तत्वों के प्रति जागरूकता के लिए 'पोषण मेले' और 'प्रोटीन-रिच प्लेट' प्रतियोगिताओं का आयोजन।

पोषण वाटिका: आंगनवाड़ी एवं घरों में बनी पोषण वाटिकाओं की ताजी उपज को पूरक आहार में शामिल करने के लिए जन-जागरूकता।

2 आंगनवाड़ी में ताजा गर्म पका भोजन

साप्ताहिक मेन्यू चक्र: स्थानीय खाद्य पदार्थों, बाजरा/मिलेट्स और मौसमी सब्जियों को शामिल करते हुए साप्ताहिक मेन्यू रोटेशन का प्रभावी क्रियान्वयन।

गर्म पके भोजन को चखने और परखने के सामुदायिक सत्र
एसएनपी मानकों के अनुसार स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और अभिभावकों के साथ सामुदायिक टेस्टिंग सत्र।

3 सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही

आंगनवाड़ी प्रबंधन समितियां: 23 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत गठित आंगनवाड़ी समितियों को सक्रिय करना और पोषण माह के दौरान अनिवार्य रूप से कम से कम एक बैठक आयोजित करना।

मेन्यू बोर्ड का अनिवार्य प्रदर्शन: सभी केंद्रों पर टेक-होम राशन के मेन्यू बोर्ड लगाना, जिससे लाभार्थियों को अधिकारों की स्पष्ट जानकारी मिले।

खाने की गुणवत्ता पर समुदाय की निगरानी: माताओं की समितियों और आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और नियमितता की सीधी निगरानी।

4 पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास

संशोधित होम विजिट शेड्यूल
शून्य से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 34 विकासात्मक माइलस्टोन आधारित संशोधित होम विजिट शेड्यूलर का क्रियान्वयन।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल
मस्तिष्क विकास और स्कूल पूर्व तैयारी के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा।

समय से स्क्रीनिंग व रेफरल: ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की समय पर स्क्रीनिंग व रेफरल।

5 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 सफल वर्ष

शत-प्रतिशत कवरेज: सभी पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पंजीकरण, पेंडेंसी क्लीयरेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तेजी से निस्तारण के लिए विशेष अभियान।

जागरूकता एवं टूलकिट: योजना की पात्रता और किश्तों के प्रति प्रचार-प्रसार तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 'PM-MVY टूलकिट' का विमोचन।

बोर्ड' अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 2026 केवल एक सरकारी कार्यक्रम न होकर जनभागीदारी का उत्सव है, जहां समाज का प्रत्येक वर्ग आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी और सुपोषण के निर्माण में अपनी सीधी जिम्मेदारी निभाएगा। जीवन के पहले 1,000 दिनों के दौरान अच्छा पोषण और संवेदनशील देखभाल मस्तिष्क के सर्वोत्तम विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने जीता आर्थिक मोर्चा

भारत का बढ़ता आर्थिक आत्मविश्वास... 7.8% रफ्तार से बढ़ी अर्थव्यवस्था

नागरिकों के आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार के लिए कई सुधार किए। सुधार और कुशल प्रबंधन से मिले परिणाम का ही नतीजा है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है बल्कि वैश्विक चुनैतियों के बीच भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अप्रैल-जून की तिमाही में 7.8% की रफ्तार से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था, देशवासियों के सामूहिक सामर्थ्य को करती है प्रदर्शित...

वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भी जारी रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में यह 7.8% की दर से बढ़ी। यह तेजी भारत के रिर्जव बैंक के अनुमान से भी ज्यादा रही है। इस तिमाही में रिजर्व बैंक ने 7% की विकास दर हासिल करने का अनुमान लगाया था। हालांकि, 31 अगस्त को जब आंकड़े आए तो तेजी उम्मीदों से ज्यादा रही। एक साल पहले इसी समयावधि में भारत की विकास दर 6.9% से बढ़ी थी।

भारत एक बार फिर से खिल उठा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने पर देश को बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में जीडीपी के मजबूत आर्थिक आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये आंकड़े देश के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की शानदार

नागरिकों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सफलता पर कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 7.8% की वृद्धि का अनुमान है।

10.3% की वृद्धि का अनुमान है इसी समयावधि में नॉमिनल जीडीपी में।

8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है वास्तविक जीवीए में।

उन्होंने कहा कि इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय भारत के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन अच्छे परिणाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, हमारे सभी नागरिकों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

7.8% की वृद्धि। मजबूत आंकड़े। और भी अधिक आत्मविश्वास।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

लगातार मजबूत हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लगातार मजबूत हो रही है। एक बार फिर, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल की है। यह पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है, जिसने हमारे देश को ऐसी मजबूती दी है कि वैश्विक स्तर पर चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, हम सफल होकर उभरते हैं। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं।

जीडीपी ग्रोथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों की सामूहिक ताकत ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद भारत तेजी से विकास करता रहे। उन्होंने कहा कि निराशावादी लोगों की हार हुई और भारत एक बार फिर से खिल उठा है।

अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ पीएम का संवाद

अंतरिक्ष में भारत की युवा शक्ति

'सेवा तीर्थ' में 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 स्पेस स्टार्टअप प्रमुखों से मुलाकात कर उनके नए प्रयोगों की तारीफ की। साथ ही, उन्होंने बच्चों में स्पेस साइंस के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को 'अटल टिंकरिंग लैब' से जुड़ने का किया आग्रह...

देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। सरकार के इस निर्णय से उद्योग जगत उत्साहित हैं क्योंकि इससे इनोवेशन के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। स्पेस स्टार्टअप के सीईओ और संस्थापकों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर की नई तकनीकों और उनसे मिलने वाले फायदों को अपनाने में कई कंपनियों ने गहरी रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्योगों द्वारा दिखाए विश्वास ने उस विकासदृष्टि को और सुदृढ़ किया है जिसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया था।

पीएम मोदी ने स्पेस कंपनियों से कहा कि वे अपनी तकनीक के नए इस्तेमाल खोजें और लोगों का जीवन आसान बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने अपील की कि बच्चों और युवाओं में स्पेस के प्रति उत्सुकता जगाने के लिए ये कंपनियां 'अटल टिंकरिंग लैब्स' के साथ मिलकर काम करें।

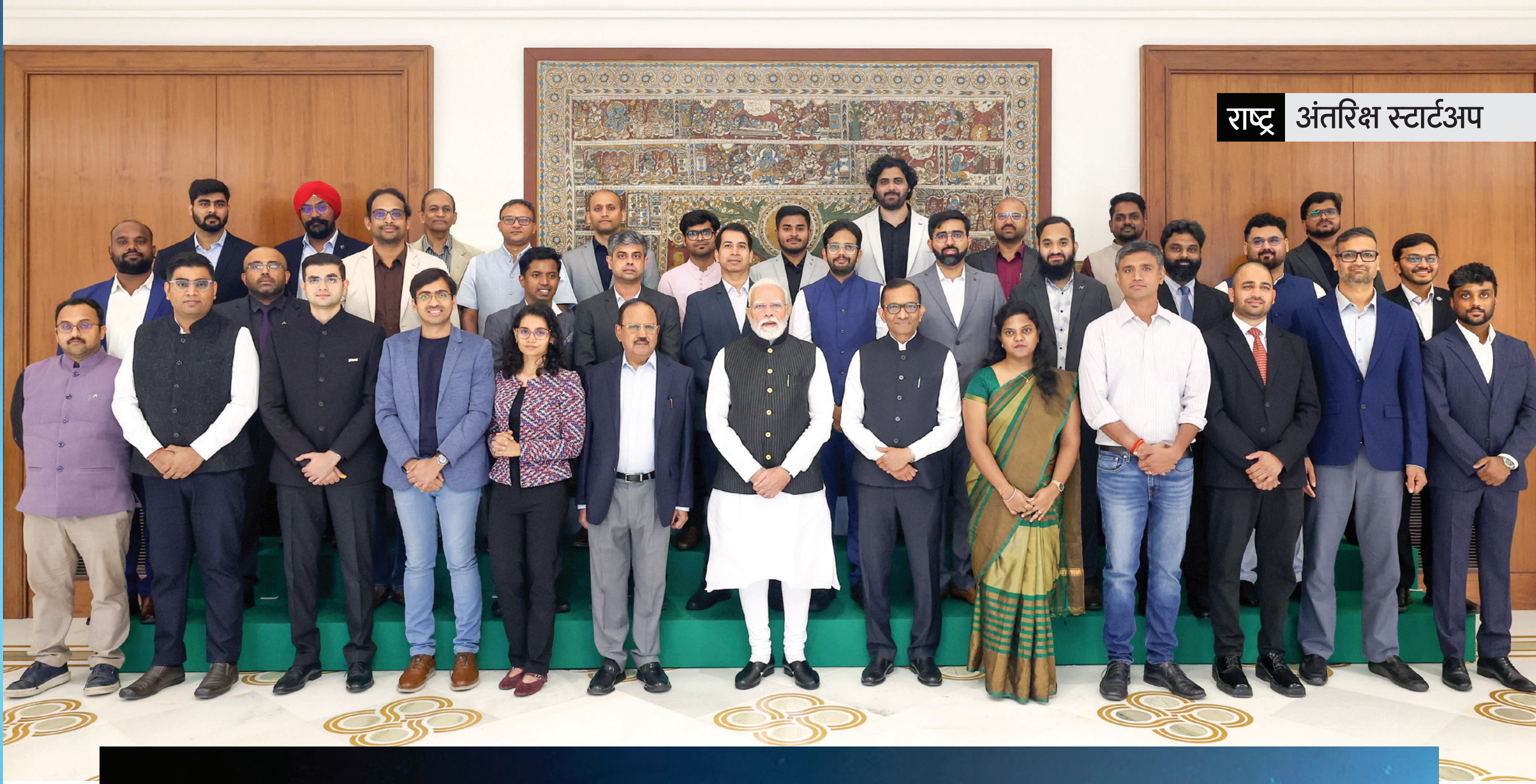

“

कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है। उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इन स्टार्टअप के संस्थापक और सीईओ संवाद में शामिल

संवाद कार्यक्रम में स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सल, ध्रुवा स्पेस, गैलेक्सीआइ, पियरसाइट, बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस, दिगांतारा, सैटश्योर, सुहोरा टेक्नोलॉजीज, मनस्तु स्पेस, एस्ट्रोबेस, टेकमी2स्पेस, व्योमआईसी, कॉस्मोसर्व स्पेस, ऑर्बिट एड एयरोस्पेस, स्काईसर्व (हाइस्पेस), सेरेन्डिपिटी स्पेस, वासर लैब्स और मिस्टईओ।

विश्वास पैदा करने का था प्रयास

संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पर भरोसा किया। मेरा एक मत रहा है कि जो भी निर्णय करें, उसमें कंसिस्टेंट रहें। बार-बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। यही विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास था।

विदेश गए हुए लोग आ रहे हैं वापस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की दुनिया से बहुत लोगों को जोड़ना है और अब विदेश गए हुए लोग वापस आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक वातावरण तैयार करना चाहिए कि इस क्षेत्र में दुनियाभर के लोगों को लगे कि जिंदगी बनानी है, तो हिंदुस्तान जाओ। भारत के किसी स्टार्टअप से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं, पूरा टैलेंट पूल, एक मैग्नेट की तरह आपके कारण खींच सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। ■

पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

'इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026'

रिफॉर्म्स... बाध्यता नहीं प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास

मैन्युफैक्चरिंग, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन एवं ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, ये सात सेक्टर्स ऐसे हैं, जिस पर आज भारत का बहुत फोकस है। यही कारण है कि भारत पॉलिसी लेवल पर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। 21 अगस्त को 'इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह रिफॉर्म्स हमारे लिए बाध्यता नहीं, है हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास...

हर रिफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले सोचने के तरीके से ही होती है। जहां पहले उत्पादन बढ़ाने पर सजा मिलती थी, वहीं आज केंद्र सरकार उत्पादन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। आज पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। 'इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब ढाई लाख करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का उत्पादन और बिक्री हुई है। 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निर्यात हुआ है और 14 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां बनी हैं। पहले, लाइसेंस राज में पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का इंसेंटिव मॉडल लाखों नई नौकरियां सृजित कर रहा है।

आज देश में तेज विकास और सुधार इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि भारत में राजनीतिक स्थिरता है। देश की नीति में निरंतरता है। पहले देश में रिफॉर्म्स की घोषणा तो होती थी लेकिन बाद में उसे भूल जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है- गवर्नेंस लेवेल के रिफॉर्म्स हों! इसके लिए, आज 21वीं सदी के भारत में, सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं। पहले रेगुलेशन की अप्रोच थी- "जब तक अनुमति न हो, तब तक प्रतिबंधित।" यानी जब तक सरकार इजाजत न दे, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस अप्रोच को बदलकर, "जब तक मना न हो, तब तक अनुमति है" की तरफ ले जा रहे हैं। यानी, जो काम कानून ने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, उसके लिए हर कदम पर अनुमति की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे सोच बहुत सीधी है, सरकार और नागरिक के रिश्ते का आधार, संदेह नहीं, विश्वास होना चाहिए।

> *आने वाले समय में इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस का और विस्तार होगा। देश के युवा, नारी शक्ति, किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस और अधिक गति से आगे बढ़ने वाली है।*
>
> *- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

समय के साथ बदलते भारत की पहचान

दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा यात्री इसमें यात्रा कर चुके हैं। साथ ही इसकी पंक्चुअलिटी 99.9% है। वक्त बदला है। इसी तरह, दिल्ली मेट्रो की पंक्चुअलिटी 99.9% है। ये पंक्चुअलिटी, न्यूयार्क, हांगकांग और पेरिस जैसे शहरों की मेट्रो से करीब-करीब बराबर हो चुकी है।

बढ़ रहा डिफेंस एक्सपोर्ट

भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी तरह, डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म किया गया। 200 साल के पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदला है। 40 से ज्यादा आयुध फैक्ट्री को मर्ज कर 7 फैक्ट्री बनाई गई। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है और 2014 की तुलना में, रक्षा निर्यात 55 गुना बढ़ा है।

सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर की बदली तस्वीर

आज सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, पुलों और सुरंगों का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 2024 और 2025 में ही, बीआरओ के 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली, तो सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भी बदल गई।

करोड़ों यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का अभियान

2014 से पहले ट्रेनों में जहां लगभग 12 हजार बायो-टॉयलेट्स लगाए गए थे, वहीं उसके बाद ट्रेनों में 3 लाख 60 हजार से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स लगाए गए हैं। यानी, 97% से ज्यादा बायो-टॉयलेट्स पिछले 12 वर्षों में लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ सफाई का नहीं, यात्रियों की गरिमा, स्वच्छता और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में गवर्नेंस का एक नया मॉडल है। ये करोड़ों यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का अभियान भी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'खेलो इंडिया डायलॉग' में युवाओं को किया संबोधित

खेल : युवा शक्ति को साथ जोड़ने का अभियान

भारत में जब खेल की बात होती है तो वह केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं होता बल्कि वह विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान होता है। खेल केवल मैदान पर जीतना नहीं सिखाता, यह हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में काफी काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को 'खेलो इंडिया डायलॉग' में युवाओं को किया संबोधित...

एक स्वस्थ समाज, अच्छी पारिवारिक व्यवस्था और बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। यह स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना नहीं सिखाता, बल्कि एक बेहतर प्रतिस्पर्धी बनना भी सिखाता है। उठना, गिरना... गिरकर फिर से उठना... यह जज्बा हमारे भीतर लाता है। 'खेलो इंडिया डायलॉग' में युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा था। मैं हमेशा कहता आया हूं - जो खेले, वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और

पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

> *"सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक खेल इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज खेल विश्वविद्यालय से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने में हर स्तर पर सहयोग मिले।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

नए विचार ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत

खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है। यह एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक-एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। इसके साथ जो युवा संवाद हुआ, वो कार्यक्रम प्रतिभागियों के विचारों और आकांक्षाओं को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या हैं, इन बातों को सुना जा रहा है और उसे नीति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इसलिए, आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए विचारों को आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए विचार ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे।

5,000+

स्थानों पर युवाओं ने खेल को लेकर अपने विचार और सपने साझा किए।

खेलो इंडिया डायलॉग के तहत 'युवा संवाद' में पांच मुख्य थीमों पर ध्यान केंद्रित किया गया- खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशामुक्त युवा।

दुनिया का बदलता है नजरिया

जब कोई खिलाड़ी सफल होता है, तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती, उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत होती है। यानी दुनिया उस खिलाड़ी के नाम से उस शहर या राज्य को पहचानने लगती है। और जब ऐसी अनेक सफलताओं को लेकर कोई क्षेत्र ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर चमकता है, तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है।

देश का गौरव बढ़ाना।

स्पोर्ट्स, एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो असली खिलाड़ी होते हैं, उनमें ड्रग्स, नशे से दूर रहने की इच्छाशक्ति भी पैदा हो जाती है। आज जब नशे की इतनी बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है, तो स्पोर्ट्स इसमें भी बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। ■

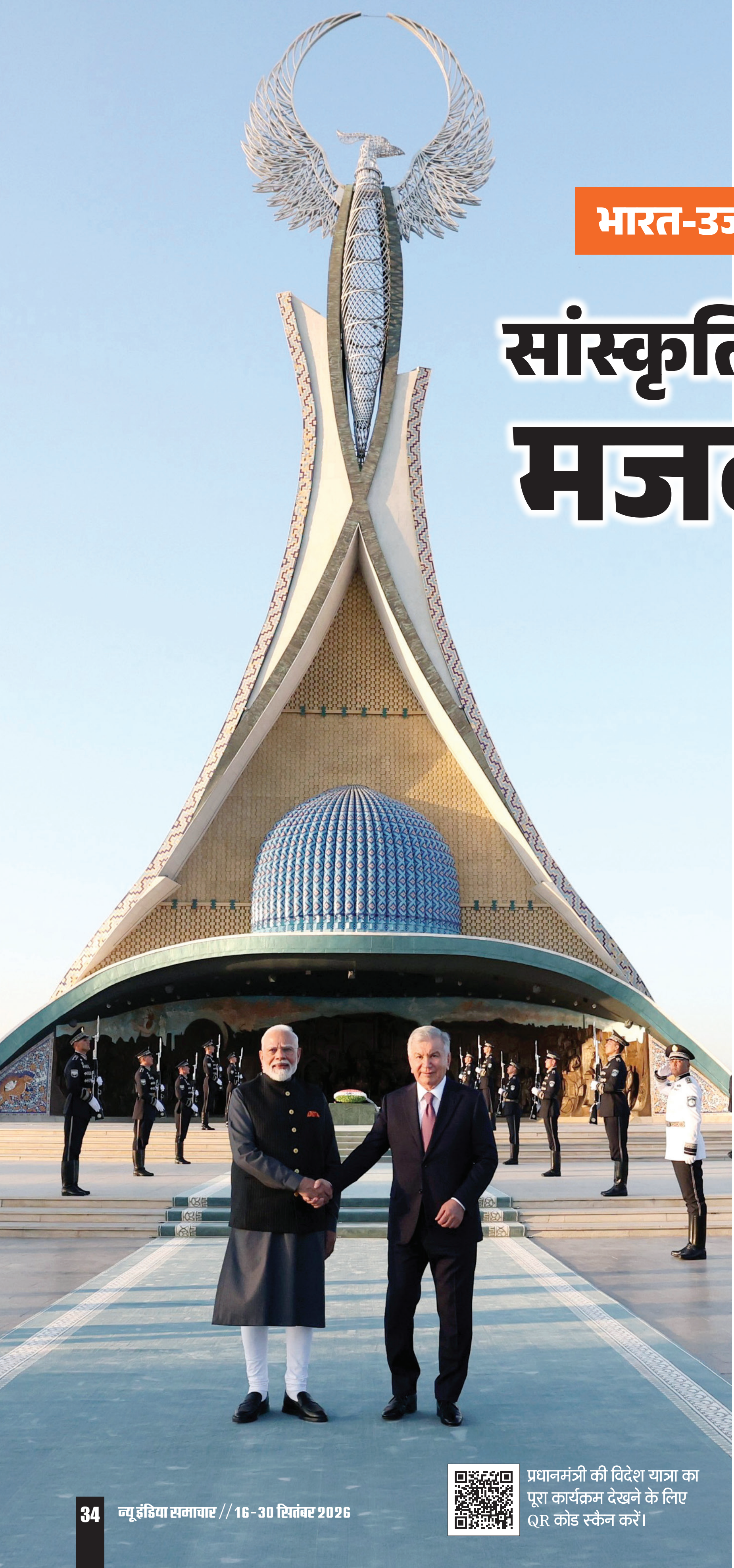

भारत-उज्बेक-किर्गिज संबंध

सांस्कृतिक जुड़ाव की मजबूत डोर

भारत और मध्य एशियाई देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नए आयाम देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की (29 अगस्त से एक सितंबर तक) उज्बेकिस्तान और किर्गिजस्तान की यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देना रहा। साथ ही, पूरे क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की चुनौतियों से मुक्त कर एक सुरक्षित माहौल तैयार करना रहा। साथ ही शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी ने क्षेत्रीय संवाद और बहुपक्षीय साझेदारी को प्रदान की नई ऊर्जा...

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने 2026-2030 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अभिलेखागार सहयोग का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण, अध्ययन और जीर्णोद्धार के लिए शोध संस्थानों, संग्रहालयों और विशेषज्ञों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके तहत सांस्कृतिक धरोहरों का डिजिटलीकरण, 3D मॉडलिंग और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने प्राचीन बौद्ध स्थलों 'फयाज टेपा' और 'कराटेपा' के संरक्षण व जीर्णोद्धार के लिए हुए समझौते की सराहना की।

भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी यात्रा थी और पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी की यहां के राष्ट्रपति के साथ 10 से ज्यादा बार मुलाकात हो चुकी है। इस वर्ष दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लिहाजा दोनों देशों ने अपने संबंधों को कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। भविष्य की दृष्टि से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल, क्लीन एनर्जी, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दोनों देश अपने-अपने अनुभवों के आधार पर खाद्य सुरक्षा में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परंरागत चिकित्सा में भी दोनों देशों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान के बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। खेलकूद में भी साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। कुराश और कबड्डी जैसे परंपरागत खेल इस साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे।

दोनों नेताओं ने एक जैसी सोच और मध्य एशिया के बढ़ते महत्व की सराहना की। आज के जटिल वैश्विक माहौल में, उन्होंने एक स्वतंत्र, खुली और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव द्वारा दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए 'ओली दाराजली दोस्तलिक' (सर्वोच्च मित्रता सम्मान) से सम्मानित किया गया। यह उज्बेकिस्तान का विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को दोनों देशों और सभ्यताओं के बीच अटूट मित्रता का प्रतीक बताया।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृति की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी केंद्र में शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल इंडोलॉजिस्ट और विद्वानों से बातचीत की। अपनी राजकीय यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने उज्बेक विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा हेतु 'लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृति' की घोषणा की। इस वर्ष इस विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उज्बेक और हिंदी भाषाओं में 3,000 से अधिक शब्द समान हैं।

दिया। दोनों देशों ने अपनी मजबूत रणनीतिक साझेदारी और समझौतों के आधार पर भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए दीर्घकालिक सहयोग का संकल्प दोहराया। साथ ही, उन्होंने व्यापार, निवेश, परिवहन संपर्क, डिजिटल तकनीक (आईटी, एआई, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा), ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दवा उद्योग और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राजनीतिक बातचीत एवं आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई।

इन विषयों पर हुए समझौते...

- भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्ष 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
- बीच टर्मेज स्थित प्राचीन बौद्ध स्थलों फयाज टेपा और कारा टेपा के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर।
- अभिलेखीय कार्य क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।
- भूविज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्ष 2026-28 की साझेदारी।
- आर्थिक एवं वित्तीय संवाद के लिए समझौता।
- पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग।
- शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।

घोषणाएं...

- भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाना।
- अरल सागर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान।
- हिंदी भाषा के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति।
- ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में आईसीसीआर संस्कृत चेयर।
- भारत के यूपीआई एप को उज्बेकिस्तान में व्यापारियों को भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय क्यूआर-यूजेडक्यूआर को स्कैन करने में सक्षम बनाया जाएगा।
- द्विपक्षीय व्यापार एक अरब डॉलर पार कर चुका है। जिसे 2030 तक पांच अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया गया है।

एससीओ शिखर सम्मेलन

विजन को वास्तविकता में बदलने का समय

26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में एससीओ ने सहयोग की मजबूत नींव तैयार की है। अब आने वाले 25 वर्षों में एससीओ का लक्ष्य इस सहयोग को स्पष्ट परिणामों में बदलने का होना चाहिए। पीएम मोदी ने एससीओ की पिछली बैठक में भारत की सोच के तीन स्तंभों (एस-सेक्योरिटी, सी-कनेक्टिविटी और ओ-अपॉर्चुनिटी) का किया जिक्र...

- **शांति और सुरक्षा :** आतंकवाद आज पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके विरुद्ध लड़ाई में एक्शन और रिएक्शन की सोच से आगे निकल कर इसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधक बनाते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा। पश्चिम एशिया के संकट ने यह दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र का संघर्ष वहीं तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और सप्लाईचेन पर पड़ता है। इसका सबसे अधिक खामियाजा ग्लोबल साउथ के देशों को भुगतना पड़ता है। इसलिए भारत का आह्वान रहा है कि सभी तनावों और युद्धों का समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं, बातचीत और कूटनीति से ही संभव है।

- **मजबूत और विश्वसनीय कनेक्टिविटी :** भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है, जो बाजार को जोड़ते हैं। व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी अत्यंत आवश्यक है।

> *डग ट्रैफिकिंग केवल एक अपराध नहीं है बल्कि युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। एससीओ के अंतर्गत सुरक्षा खतरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सूचना सुरक्षा और नारकोटिक्स जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित किए जा रहे सेंटर एक सकारात्मक कदम है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

- **अवसर :** सबसे बड़ी पूंजी लोगों के बीच आपसी संबंध हैं। भारत के लिए एससीओ महान सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों का संगम है। एससीओ के अगले पच्चीस वर्षों में सदस्य देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंध को सहयोग के केंद्र में रखना चाहिए।

पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक

बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी हित के अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। विचारों में पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का मुद्दा शामिल रहा, जिनका समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर असर पड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही रास्ता है। दोनों नेता अपने देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं की इस साल की यह पहली मुलाकात थी। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई जिसमें द्विपक्षीय के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

भारत ने एससीओ में स्टार्टअप फोरम, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव और यंग साइंटिस्ट फोरम की शुरुआत की है।

- **20 से अधिक निर्णय :** बिश्केक घोषणा-पत्र के अलावा, इस शिखर सम्मेलन में जलवायु, परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और मादक पदार्थों की लत से निपटने जैसे क्षेत्रों में चार समझौता-ज्ञापन तथा बीस से अधिक निर्णय व वक्तव्य स्वीकार किए गए।

मजबूत होता क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर

भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों का एक विस्तृत नेटवर्क है। 20 हजार किलोमीटर लंबा यह नेटवर्क 23 राज्य और चार केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। अभी 32 राष्ट्रीय जलमार्ग ऑपरेशनल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 5 वर्ष के विशेष लक्ष्यों के साथ शुरू क्रूज भारत मिशन के 30 सितंबर को दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चरणबद्ध ऑपरेशनल करने की घोषणा की है...आइए जानते हैं किस तरह हो रहा है जलमार्गों पर नौकायन का विकास...

देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितंबर 2024 को शुरू क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है। साथ में, पांच वर्षों में 10 समुद्री क्रूज टर्मिनल, 100 नदी क्रूज टर्मिनल और 5 मरीना की स्थापना करना है। अगर बीते 12 वर्षों की बात करें तो समुद्री क्रूज यात्रियों की संख्या में 300 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में समुद्र क्रूज यात्रियों की संख्या 1.08 लाख थी जो 2025-26 में बढ़कर 4.62 लाख हो गई है। अगले एक दशक में भारतीय क्रूज बाजार में आठ गुना वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। मिशन के पहले चरण के तहत अध्ययन, मास्टर प्लानिंग और पड़ोसी देशों के साथ क्रूज साझेदारी के साथ वर्तमान टर्मिनल का आधुनिकीकरण करने का काम तेज गति से चल रहा है। आगे के दो चरणों के लिए सरकार ने 19 नए जलमार्गों के ऑपरेशनल करने का खाका भी चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पेश किया है।

क्रूज भारत मिशन और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जैसी प्रमुख पहलों के साथ, सरकार भारत को वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक मजबूत नींव रख रही है। केरल के शांत बैकवाटर से लेकर राजसी गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र के प्राचीन विस्तार तक, क्रूज पर्यटन न केवल नई आर्थिक संभावनाओं को खोल रहा है, बल्कि रोजगार सृजन की नई संभावनाएं भी बढ़ा रहा है।

क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कदम

- पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पत्तनों पर क्रूज जलयानों के लिए एसओपी-3 जारी की।
- विशाखापत्तनम (सितंबर 2023), मुंबई (सितंबर 2025) और चेन्नई (जून 2026) में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल को उन्नत और चालू किया गया है।
- पुडुचेरी के साथ पूर्वी तट क्रूज सर्किट का विस्तार किया गया है।
- सभी नौ क्रूज गंतव्यों सहित गुजरात समुद्री बोर्ड में गंतव्य कार्य बलों का गठन किया गया।
- क्रूज पोतों के लिए क्यूआर-आधारित इमिग्रेशन प्रणाली शुरू की गई है।
- त्वरित सीमा शुल्क निकासी के उद्देश्य से क्रूज पोतों के लिए डिजिटल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और स्व-घोषणा तंत्र आरंभ किया गया।
- विदेशी पर्यटक समूहों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ग्रुप यात्रा वीजा शुरू किया।
- विदेशी क्रूज के लिए कैबोटेज माफ किया।

साहस, करुणा और दृढ़ विश्वास की प्रतिमूर्ति

समाज सुधारिका रानी रासमणि ने न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देकर अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि जन-कल्याण के लिए जीवन भर काम करती रहीं। इतना ही नहीं, साहस, करुणा और दृढ़ विश्वास की प्रतिमूर्ति रानी ने बहु विवाह पर रोक लगाने वाले कानून के लिए गंभीरता से काम किया। विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कर जहां उन्होंने आध्यात्मकिता का परिचय दिया वहीं गरीबों के उत्थान के लिए जीवनपर्यंत करती रही काम...

जन्म : 28 सितंबर 1793, मृत्यु : 19 फरवरी 1861

बात है 1850 की, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत पर कब्जा जमाए बैठी थी। उस समय एक महिला अपने अधिकार के लिए अंग्रेजों के सामने एक चुनौती बन कर आई। यह महिला कोई और नहीं बल्कि रानी रासमणि थी जिन्होंने न सिर्फ महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया बल्कि समाज की बुराईयों के खिलाफ आवाज भी उठाती रहीं।

28 सितंबर 1793 को 'कोना' गांव (जो अब नदिया-उत्तर 24 परगना सीमा पर है) में एक महिष्य किसान परिवार में जन्मीं रानी रासमणि को शुरुआती जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वह केवल सात साल की थीं तभी उनकी मां का निधन हो गया। ऐसे में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वह 11 साल की हुई तो कोलकाता के जानबाजार के एक अमीर जमींदार परिवार के बाबू राजचंद्र दास से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1836 में पति की मृत्यु के बाद, रासमणि ने जमींदारी और आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी संभाली और अपनी प्रबंधन क्षमता और समाज-सेवा के कार्यों से लोगों का सम्मान और प्यार हासिल किया।

समाज-सेवा और सामाजिक योगदान के लिए पहचान रखने वाली रानी रासमणि ने 1847 और 1855 के बीच प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण करवाया जिसके लिए उन्होंने 30,000 एकड़ जमीन खरीदी और इस प्रोजेक्ट में आठ साल और नौ लाख रुपये लगाए। उन्होंने गंगा किनारे घाटों और तीर्थयात्रियों के लिए सड़कों के निर्माण के लिए भी पैसे दिए और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और हिंदू कॉलेज (अब प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी) जैसे संस्थानों में भी योगदान दिया।

इतना ही नहीं, अपने साहस के लिए पहचान रखने वाली रानी रासमणि कई मौकों पर ब्रिटिश अधिकारियों के सामने डटकर खड़ी हुईं। उन्होंने गंगा में मछली पकड़ने पर लगने वाले टैक्स को चुनौती दी। धार्मिक जुलूसों पर लगी रोक का विरोध किया, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और परंपराओं की सफलतापूर्वक रक्षा हुई। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर कई सुधारों को आगे बढ़ाया, जिनमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भी शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुविवाह के खिलाफ एक ड्राफ्ट बिल सौंपा। 19 फरवरी 1861 को उनका निधन हो गया। रानी रासमणि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "रानी रासमणि साहस, करुणा और दृढ़ विश्वास की महान प्रतिमूर्ति थीं। उन्हें दूरदर्शी नेता और परोपकारी महिला के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने स्थायी संस्थाओं का निर्माण किया। आध्यात्मिकता के साथ-साथ गरीबों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी।"

PMO India @PMOIndia

खेल हमें केवल champion बनना नहीं सिखाता... बल्कि खेल हमें एक बेहतर competitor बनना भी सिखाता है।

उठना, गिरना... गिरकर फिर से उठना... Sports, ये ज़ज्बा हमारे भीतर लाता है: PM @narendramodi

Rajnath Singh @rajnathsingh

ITI को केवल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, India के Industrial Transformation की फाउंडेशन बनाना है। PM-SETU के तहत इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप Curriculum, Equipment और Apprenticeship को मजबूत कर युवाओं को रोजगार-रेडी बनाना होगा। आत्मनिर्भर डिफेन्स इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर Talent Pipeline जरूरी है।

Amit Shah @AmitShah

नेपाल में आई बाढ़ की विभीषिका अत्यंत दुःखद है। जिन परिवारों ने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ खड़ी है।

नेपाल में आई इस आपदा के संबंध में बिहार व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की। इसका प्रभाव जिन सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ सकता है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव की टीमों के साथ NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

From taking banking to every doorstep to empowering millions with access to formal finance, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has transformed India's financial inclusion landscape. In 12 years, 59 crore accounts, with 56% held by women, have become gateways to savings, insurance, credit and Direct Benefit Transfers. This remarkable transformation reflects the visionary leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji and his unwavering commitment to inclusive growth and a Viksit Bharat.

Manohar Lal @mlkhattar ·

UPI has transformed how India transacts, bringing speed, simplicity, and inclusion to everyday payments.

From street vendors to small businesses, it has expanded access to the formal economy, strengthened transparency, and positioned India as a global leader in digital payments.

Kiren Rijiju @KirenRijiju

कभी लगती थी लंबी कतार... अब बस एक QR!
#UPI और डिजिटल पेमेंट ने भुगतान को बनाया आसान, तेज़ और सुविधाजनक।
शॉपिंग से रोज़मर्रा के भुगतानों तक, डिजिटल इंडिया ने बदली Ease of Life की कहानी!

#DigitalIndia #10YearsOfUPI #EaseOfLiving #NewIndia

एससीओ घोषणापत्र : भारत-रूस-चीन ने कहा, नागरिकों की मौत, अर्थव्यवस्था की तबाही गलत

आतंकवाद पर दोहरा मानदंड नहीं चलेगा ईरान पर अमेरिकी हमले की भी कड़ी निंदा

अमर उजाला ब्यूरो\एजेंसी

नई दिल्ली\बिश्केक। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों ने साझा घोषणापत्र में ईरान पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड को अस्वीकार्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एससीओ के अन्य नेताओं के हस्ताक्षर वाले घोषणापत्र में कहा गया है, अमेरिकी हमलों के कारण कई लोगों की मौत हुई और ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है।

घोषणापत्र में भारत की चिंता को महत्व देते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड को अस्वीकार्य बताया और कहा, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद से लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाए, जिसमें आतंकियों की सीमा-पार आवाजाही भी शामिल है। एससीओ में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज गणराज्य शामिल हैं।

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी।

मोदी, जिनपिंग और पुतिन में दिखी गर्मजोशी

एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की एक-दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए तस्वीर चर्चा में रही।

■ एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अस्थिर रवैये व टैरिफ धमकियों के कारण कई देश परेशान हैं, वहीं यह तस्वीर वैश्विक कूटनीति में हमारी ताकत दर्शाती है।

>> 4 समझौते और 13 नतीजे : पेज 13

आतंकवाद का पोषण-तंत्र नष्ट करें : मोदी

इससे पहले पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा, इस संगठन को आतंकवाद के पूरे पोषण-तंत्र और उसकी फंडिंग को खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकियों की भर्ती, कट्टर सोच व सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करना होगा। हमें एक स्वर में बोलना होगा कि इस विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। मोदी ने दोहराया, युद्धों व संघर्षों का समाधान वार्ता व कूटनीति के जरिये किया जाना चाहिए।

■ **आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक ताकत नहीं बन सकता :** बिना पाकिस्तान का नाम लिए मोदी ने कहा, जो देश आतंकवाद को अपनी नीति बनाते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए भी रणनीतिक ताकत नहीं हो सकता।

पीएम मोदी ने एससीओ को लेकर भारत की सोच तीन स्तंभों से समझाई। ये तीन स्तंभ हैं सुरक्षा, संपर्क और अवसर।

01 सुरक्षा : संगठित अपराध और नशे की चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित किए जा रहे केंद्र सहयोग के सकारात्मक कदम हैं।

02 संपर्क : एससीओ के बाजारों को जोड़ने के सभी प्रयासों का भारत समर्थन करता है। पर इन प्रयासों के दौरान भौगोलिक अखंडता का सम्मान जरूरी है।

03 अवसर : संगठन के आपसी सहयोग का लाभ नागरिकों तक पहुंचना जरूरी है। सफलता की कसौटी यह होनी चाहिए कि हमारे प्रयासों से युवाओं, उद्यमियों, किसानों को कितने नए अवसर मिले और सदस्य देशों के नागरिकों का जीवन कितना बेहतर हुआ।

शहबाज के भाषण में फिर सिंधु : एससीओ बैठक में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बिना सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और कहा, पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

समझौता : लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान

2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार पांच अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य

ताशकंद। उज्बेकिस्तान लंबे समय तक भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देश असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के तहत यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। खुद पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत के बाद इसकी जानकारी दी। हालांकि इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है।

पीएम ने कहा, दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला लिया। साथ ही सहयोग के सभी पहलुओं को दिशा देने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक समन्वय परिषद बनाया जाएगा। इससे पूर्व मोदी व मिर्जियोयेव के बीच व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, जरूरी खनिज, खनन, रक्षा व सुरक्षा, खेती, दवाओं, स्वास्थ्य, सूचना तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (यूपीआई समेत) व शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, दोनों पक्षों ने 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 5 अरब डॉलर तय किया है, जो अभी 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। पीएम मोदी एससीओ बैठक के लिए देर रात किर्गिस्तान पहुंच गए हैं। एजेंसी >> रक्षा उद्योग में मिलकर करेंगे काम : पेज 11

ताशकंद में पीएम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान करते राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव। एजेंसी

11 समझौते और एमओयू

दोनों देशों में 11 समझौतों व एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आर्थिक संबंधों के लिए सहयोग, उज्बेकिस्तान के फयाज तेपा और कारा तेपा जैसे बौद्ध स्थलों का भारत की ओर से जीर्णोद्धार व संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण समझौता शामिल है। माइनिंग, शिक्षा, पर्यटन और आयुर्वेद क्षेत्रों में भी समझौते हुए।

■ **30 दिन की वीजा मुक्त अवधि :** भारतीय नागरिक बिना पूर्व वीजा प्राप्त किए उज्बेकिस्तान में अधिकतम 30 दिन बिता पाएंगे।

■ राष्ट्रपति शौकत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के आपसी संपर्क, पर्यटन और व्यापार को मजबूत करने में अहम योगदान मिलेगा।

उज्बेकिस्तान में चलेगा अपना यूपीआई...समझौते के तहत भारतीय यूपीआई एप्स उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय क्यूआर स्कैन कर सकेंगे। इससे यूपीआई से उज्बेकिस्तान में भुगतान किया जा सकेगा।

पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान

पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान ने अपने देश की ओर से विदेशी नेताओं को दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर' से सम्मानित किया। पीएम मोदी को दूसरे देशों में मिलने वाले सम्मान की श्रृंखला में यह 36वां है।

■ प्रधानमंत्री ने इसे देश की 140 करोड़ जनता को समर्पित किया। पीएम ने कहा, ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

यूरेनियम को लेकर भारत के विकल्प बढ़े

उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम देता रहा है। मोदी की यात्रा के बाद अब इस दुर्लभ खनिज की लंबे समय तक निर्बाध आपूर्ति पर बात आगे बढ़ी है।

■ भारत को हर साल परमाणु बिजली घरों के लिए 1,500 से 2,000 टन यूरेनियम की जरूरत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन 600 टन ही है। बाकी कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान से आयात होता है।

■ जुलाई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है। हालांकि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता।

मोदी और पुतिन में दिखी गर्मजोशी, एक कार में पहुंचे नोमाड स्पोर्ट्स उद्घाटन स्थल

मोदी–पुतिन में सामरिक साझेदारी पर हुई बात

प्रधानमंत्री जन धन योजना का परिणाम परिवर्तनकारी : मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का प्रभाव अभूतपूर्व रहा है और इसके परिणाम परिवर्तनकारी साबित हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर सरकार के नागरिक सहभागिता मंच 'माई जीओवी इंडिया' की पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि अभूतपूर्व पैमाना और परिवर्तनकारी परिणाम! जन धन योजना का प्रभाव बेजोड़ रहा है। माई जीओवी इंडिया ने पोस्ट में कहा कि एक समय ऐसा था जब औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच इस बात पर निर्भर करती थी कि कोई व्यक्ति कहां रहता है, आर्थिक स्थिति क्या है या वह बैंक से कितनी दूर है। आज अलग तस्वीर है। करोड़ों जन धन खाते, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बैंकिंग पहुंच, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच ने इसमें बड़ा बदलाव किया है।

विश्व बांस दिवस - 18 सितंबर 2026

बांस के माध्यम से मजबूत हो रही भारत की हरित अर्थव्यवस्था

जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। वह चीज कुछ और नहीं बल्कि बांस सेक्टर है जिसमें भारत सफलता का नया आयाम गढ़ रहा है। अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से बांस को पेड़ के रूप में परिभाषित किया गया था और इससे जुड़े नियम बहुत कड़े थे। ऐसे में लोग बांस से जुड़े काम-धंधे से दूर होते गए लेकिन केंद्र सरकार ने जब बांस की परिभाषा बदली, तब देश मे हुआ बड़ा परिवर्तन...

- पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बांस की खेती, प्रसंस्करण और मार्केटिंग को बढ़ावा देता है।
- यह मिशन वित्तीय सहायता, एफपीओ के गठन और कौशल विकास के माध्यम से किसानों और एमएसएमई को सहायता प्रदान करता है।
- भारत में बांस का क्षेत्रफल 13.96 मिलियन हेक्टेयर है। 136 प्रजातियों (125 देशी और 11 विदेशी) के साथ बांस विविधता के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है।

"साल 2017 में कानून में बदलाव करके हमने बांस को पेड़ की श्रेणी से बाहर किया। जिसके नतीजे सबके सामने हैं। आज पूरे पूर्वोत्तर में बांस सेक्टर फल-फूल रहा है। लोग लगातार इनोवेशन करके इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-30 सितंबर, 2026

आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 7 सितंबर 2026, कुल पृष्ठ-44)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित